EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By- Nikhil Ranjan

Useful For Prelims

Date: 20 December 2025

देश के महान नृत्य विद्वानों में गिने जाते हैं डा. सुनील कोठारी

नृत्य इतिहासकार एवं विद्वान डा. सुनील कोठारी का जन्म 1933 में आज ही बंबई (अब मुंबई) में हुआ था। चार्टर्ड अकाउंटेंट की उपाधि प्राप्त करने के बाद भारतीय नृत्य के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। कुरावंजी और कुचिपुड़ी पर शोध करते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी कृति, सत्रीया : क्लासिकल डांस आफ असम ने वैश्विक स्तर पर इस नृत्य शैली की बेहतर समझ विकसित करने में योगदान दिया। न्यू डायरेक्शन इन इंडियन डांस, कुचिपुड़ी : इंडियन क्लासिकल डांस आर्ट सहित 20 से अधिक पुस्तकें लिखीं। 2001 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

Dainik Jagaran Page No-14

पहली बार अमेरिका में परमाणु ऊर्जा से बनाई गई बिजली

1951 में आज ही पहली बार अमेरिका स्थित ईबीआर-1 (प्रायोगिक ब्रीडर रिएक्टर-1) में परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाई गई थी। इसने 200-वाट के चार बल्ब जलाए थे। इससे यह साबित हुआ कि परमाणु विखंडन से बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इसने परमाणु ऊर्जा युग की शुरुआत की।

हावड़ा ब्रिज को निशाना बनाकर जापान ने कोलकाता पर गिराए बम

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में आज ही जापान ने हावड़ा ब्रिज को निशाना बनाकर कलकत्ता (अब कोलकाता) पर बम गिराए थे। बमबारी में कई इमारतें तबाह हो गई थीं। ब्रिटेन अपने सहयोगियों तक मदद पहुंचाने के लिए भारत की जमीन का इस्तेमाल कर रहा था।

Dainik Jagaran Page No-14

खेल मंत्रालय और एआइएफएफ को लिखा पत्र | फुटबाल | एआइएफएफ सदस्य ने प्रस्ताव को अस्वीकार्य बताया

आइएसएल ने खुद के स्वामित्व वाली लीग का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा)।

इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) क्लबों ने शुक्रवार को देश की शीर्ष स्तरीय पेशेवर फुटबाल लीग के मूलभूत पुनर्गठन का औपचारिक प्रस्ताव रखा जिसके तहत अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ) को खेल के नियामक के रूप में बरकरार रखते हुए क्लबों के स्वामित्व वाली लीग माडल के लिए स्थायी परिचालन और वाणिज्यिक अधिकार मांगे।

एआइएफएफ की कार्यकारी समिति के सदस्य अविजित पाल ने हालांकि इस प्रस्ताव को अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया। एआइएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव एआइएफएफ के अधिकारों को कमजोर करेगा। यह प्रस्ताव आइएसएल क्लबों को लीग के संचालन के लिए एक संघ के गठन की योजना प्रस्तुत करने के लिए दी गई समय सीमा के अंतिम दिन पेश किया गया। लीग का 2025-26 सत्र अभी शुरू होना बाकी है। खेल मंत्रालय और एआइएफएफ को संबोधित एक संयुक्त पत्र में क्लबों ने कहा, 'हम अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ और खेल मंत्रालय के समक्ष भारत की शीर्ष स्तरीय पेशेवर फुटबाल लीग के स्वामित्व, संचालन और परिचालन ढांचे के पुनर्गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव औपचारिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं।' उन्होंने कहा,'इस प्रस्ताव में भारत में शीर्ष स्तर की फुटबाल की निरंतरता को सुरक्षित रखने, संस्थागत शासन को मजबूत करने, लीग की दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, विश्व स्तर पर स्वीकृत सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाने के साथ एआइएफएफ को विनियमन, शासन, जमीनी स्तर के विकास और राष्ट्रीय टीम की उत्कृष्टता के अपने मूल कर्तव्य पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करने का सुझाव है।'

> *एआइएफएफ* के सीनियर सदस्य पाल ने कहा कि देश की शीर्ष लीग एआइएफएफ की है और हम उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए और आमसभा द्वारा मंजूर किए गए हमारे नए संविधान के तहत इसके आयोजन के लिए बाध्य है। चूंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है तो हमें इस मसले पर फिलहाल अलग से कोई पक्ष रखने का अधिकार नहीं है।

एआइएफएफ के सीनियर सदस्य पाल ने कहा कि इस प्रस्ताव से यह समझा जाएगा कि एआइएफएफ एक कमजोर संस्था है। मैं अनुरोध करूंगा कि शनिवार को होने वाली आमसभा की बैठक में अध्यक्ष एक समिति बनाए जो चीजों का जायजा लेकर लीग या लीगों को शुरू करने के उपाय करे। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब भारतीय फुटबाल में अनिश्चितता का माहौल है जिसमें प्रशासन संबंधी चुनौतियां, वाणिज्यिक समझौतों की समाप्ति और एआइएफएफ संविधान में संशोधन से संबंधित उच्चतम न्यायालय में चल रही कार्यवाही शामिल हैं।

Jansatta Page No-22

'नियो' रपट का दावा | बदलाव | दो-तिहाई यात्राएं दिल्ली, बंगलुरु और मुंबई से शुरू हुई

2025 में सर्वाधिक विदेश घूमने वाले 'मिलेनियल्स' और 'जेन जी'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

भारत के विदेश यात्रा परिदृश्य में वर्ष 2025 में एक निर्णायक बदलाव देखने को मिला, जिसके तहत देश से 10 में से नौ अंतरराष्ट्रीय यात्राएं 'मिलेनियल्स' और 'जेन जी' ने कीं। एक रपट में यह जानकारी सामने आई है। वर्ष 1981-1996 के बीच जन्मी पीढ़ी को मिलेनियल्स जबकि वर्ष 1997-2012 के बीच जन्मे लोगों को 'जेन जी' कहा जाता है।

यात्रा एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी मंच 'नियो' द्वारा जारी वार्षिक यात्रा रपट इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे युवा, डिजिटल-फर्स्ट और अनुभव-केंद्रित भारतीय कैसे बेहतर योजना, अकेले यात्रा और लागत-सचेत निर्णय के माध्यम से वैश्विक यात्रा प्रवृत्तियों को नया रूप दे रहे हैं। रपट के निष्कर्षों में कहा गया है, 'जेन जी और मिलेनियल्स ने 10 में से 9 अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कीं। इनमें से दो-तिहाई यात्राएं दिल्ली, बंगलुरु और मुंबई से शुरू हुईं, जो भारत के प्रमुख महानगरों के विदेश यात्रा पर मजबूत प्रभाव को दर्शाती हैं।'

> *रपट* के अनुसार, भारतीय यात्रियों में सबसे अधिक पसंदीदा एकल यात्रा रही। इस साल 63.8 फीसद लोगों ने एकल यात्राएं कीं। युगल यात्रा का फीसद 19.93 रहा। इसके बाद परिवारों की यात्रा का फीसद 12.26 एवं समूहों का फीसद 4.01 रहा।

> *रपट* में विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के खर्च पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें कुल खर्च का आधा हिस्सा खरीदारी पर हुआ, इसके बाद भोजन पर 20.69 फीसद, परिवहन पर 19.93 फीसद, आवास पर 9.09 फीसद व अनुभवों पर 3.01 फीसद खर्च हुआ।

रपट के अनुसार, भारतीय यात्रियों में सबसे अधिक पसंदीदा एकल यात्रा रही, जो एक विकल्प के तौर पर उभरी हैं। इस साल 63.8 फीसद लोगों ने एकल यात्राएं कीं। युगल यात्रा का फीसद 19.93 रहा। इसमें कहा गया है कि इसके बाद परिवारों की यात्रा का फीसद 12.26 एवं समूहों का फीसद 4.01 रहा। रपट में कहा गया है कि ये आंकड़े स्वतंत्र यात्रा अथवा एकल यात्रा की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है।

रपट में कहा गया है कि कम दूरी की एशियाई यात्रा वाले गंतव्य और उभरते मध्य एशियाई देश भारतीय यात्रियों के लिए शीर्ष विकल्प बने रहे। इसमें कहा गया है कि इस सूची में शीर्ष पर थाईलैंड रहा, जहां 23.08 फीसद यात्राएं की गईं, इसके बाद 21.57 फीसद यात्राओं के साथ यूएई का नंबर रहा। इसके अनुसार इसके बाद जार्जिया (9.65 फीसद), मलेशिया (8.89 फीसद), फिलीपींस (8.8 फीसद), कजाकिस्तान (7.38 फीसद), वियतनाम (5.87 फीसद), उज्बेकिस्तान (5.6 फीसद), ब्रिटेन (5.38 फीसद) और सिंगापुर (3.78 फीसद) की यात्राएं की गईं। इसमें आगे कहा गया है, 'यात्रा वृद्धि के मामले में उभरते देश थाईलैंड, यूएई, मलेशिया, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान थे, जबकि दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, हांगकांग और इंडोनेशिया के लिए वीजा चुकिंग में भी मजबूत वृद्धि हुई।'

रपट में विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के खर्च करने के बदलते व्यवहार पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें दिखाया गया है कि कुल खर्च का लगभग आधा हिस्सा खरीदारी पर (कार्ड के उपयोग का 47.28 फीसद) खर्च हुआ, इसके बाद भोजन पर 20.69 फीसद, परिवहन पर 19.93 फीसद, आवास पर 9.09 फीसद और अनुभवों पर 3.01 फीसद खर्च हुआ। रपट के निष्कर्ष दस लाख से अधिक विदेश यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के यात्रा आंकड़ों पर आधारित हैं।

Jansatta Page No-14

भारत के साथ संबंधों को मजबूत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप

भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने से जुड़े रक्षा नीति बिल पर किए हस्ताक्षर

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त वातावरण देने और चीन की चुनौती से निपटने के लिए क्वाड के जरिये सहयोग भी बढ़ाएंगे
- भारत के साथ न्यूक्लियर लायबिलिटी रूल्स के संबंध में परामर्श तंत्र स्थापित करेंगे

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

वाशिंगटन, प्रेट: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों में जुट गए हैं। इसी कवायद में उन्होंने एक सालाना रक्षा नीति बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें भारत के साथ साझेदारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। इस विधेयक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने और चीन से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए क्वाड के जरिये सहयोग बढ़ाने का जिक्र भी किया गया है।

ट्रंप ने गुरुवार को 'राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम वित्तीय वर्ष 2026' पर हस्ताक्षर किए। उनके हस्ताक्षर से यह कानून बन गया है। इसमें यह कहा गया है कि विदेश मंत्री अमेरिका-भारत रणनीतिक सुरक्षा वार्ता के तहत न्यूक्लियर लायबिलिटी रूल्स के संबंध में भारत सरकार के साथ एक संयुक्त परामर्श तंत्र स्थापित करेंगे। इसमें युद्ध (रक्षा) मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमों, विदेश मंत्रालय, गृह सुरक्षा मंत्रालय, खुफिया एजेंसियों और अन्य कार्यकारी विभागों व एजेंसियों के लिए वित्तीय वर्ष की राशि आवंटित करने का निर्देश भी दिया गया है। ट

ट्रंप ने बयान में कहा, 'यह कानून ताकत के जरिये शांति कायम करने के मेरे एजेंडे को लागू करेगा। घरेलू और विदेशी खतरों से मातृभूमि की रक्षा करने और रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत बनाने के लिए युद्ध मंत्रालय को सक्षम बनाएगा। इससे उन फिजूल और कठोर कार्यक्रमों के लिए धन मुहैया कराने पर लगाम लगेगी, जिनसे हमारे देश के सैन्य कर्मियों की युद्ध लड़ने की भावना कमजोर होती है।'

अधिनियम में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा गठबंधनों और साझेदारियों को लेकर संसद के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है।

इसके तहत रक्षा मंत्री को ऐसे प्रयास जारी रखने चाहिए, जिनसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के रक्षा गठबंधन और साझेदारियां मजबूत हों ताकि चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में अमेरिका को बढ़त मिल सके।

भारत-अमेरिका साझेदारी को बढ़ावा: अधिनियम में क्वाड के जरिये मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा उद्देश्य को बढ़ावा देना, द्विपक्षीय व बहुपक्षीय संबंधों, सैन्य अभ्यासों में भागीदारी, विस्तारित रक्षा व्यापार, मानवीय सहायता एवं आपदा प्रतिक्रिया को लेकर सहयोग और समुद्री सुरक्षा को लेकर अधिक सहयोग प्रदान करके भारत-अमेरिका साझेदारी को बढ़ावा देना शामिल है। 2017 में गठित चार देशों के इस समूह में भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है।

ट्रंप प्रशासन छीन सकता है विदेश में जन्मे अमेरिकियों की नागरिकता

वाशिंगटन, एपी : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ग्रीन कार्ड लाटरी कार्यक्रम को निलंबित कर दिया। दरअसल, इसी कार्यक्रम के तहत ब्राउन यूनिवर्सिटी और एमआइटी गोलीबारी का संदिग्ध अमेरिका आया था। गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने कहा कि ट्रंप के निर्देश पर वह अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा को कार्यक्रम रोकने का आदेश दे रही हैं।

उन्होंने पुर्तगाली नागरिक क्लाउडियो नेवेस वैलेंते के बारे में कहा, "इस व्यक्ति को हमारे देश में प्रवेश ही नहीं दिया जाना चाहिए था।" वैलेंते पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी का संदेह है, जिसमें दो छात्रों की मौत हो गई थी और नौ अन्य घायल हुए थे। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि उसी ने एमआइटी के प्रोफेसर की हत्या भी की थी। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार शाम को उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, नेवेस वैलेंते ने 2000 से छात्र वीजा पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। 2017 में उसे डायवर्सिटी वीजा प्रोग्राम जारी किया गया और कुछ महीनों बाद कानूनी तौर पर स्थायी निवास का दर्जा दे दिया गया। डायवर्सिटी वीजा प्रोग्राम के तहत हर साल लाटरी के माध्यम से उन देशों के लोगों को 50,000 तक ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनका अमेरिका में प्रतिनिधित्व बहुत कम है। ट्रंप लंबे समय से इस लाटरी का विरोध किया है।

2028 तक चंद्रमा पर अंतरिक्षयात्री भेजने का लक्ष्य

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अंतरिक्ष में देश का दबदबा बनाए रखने को लेकर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें 2028 तक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखने के साथ अंतरिक्ष को हथियारों से सुरक्षित रखने की बात भी है। 2030 तक चंद्रमा पर स्थायी आउटपोस्ट बनाने की योजना भी है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अंतरिक्ष नीति को लेकर यह पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। यह आदेश अरबपति निजी अंतरिक्षयात्री और पूर्व स्पेसएक्स कस्टमर जेरेड इसाकमैन के नासा के 15वें प्रशासक के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटे बाद जारी किया गया।

Dainik Jagaran Page No-11

गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा बैठक

बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो बनेगा, समय पर होगा सूचनाओं का विश्लेषण

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

केंद्र सरकार बंदरगाहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने लिए एक वैधानिक निकाय के तौर पर 'बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो' का गठन करेगी। यह निकाय बंदरगाहों और जहाजों से जुड़ी सुरक्षा संबंधी सूचनाओं का समय पर विश्लेषण, संग्रहण और आपसी आदान-प्रदान सुनिश्चित करेगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि ब्यूरो साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगा।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बंदरगाहों और जहाजों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित निकाय के गठन के संबंध में बैठक बुलाई, जिसमें बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी उपस्थित हुए। शाह ने देश में एक मजबूत बंदरगाह सुरक्षा ढांचे की आवश्यकता पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि सुरक्षा उपायों को क्रमबद्ध और जोखिम-आधारित तरीके से लागू किया जाए। बयान में कहा गया कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि समुद्री सुरक्षा ढांचे से प्राप्त अनुभवों को विमानन सुरक्षा क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा।

बयान के अनुसार, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की तर्ज पर बनाए जाने वाले बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो (बीओपीएस) का एक महानिदेशक होगा और यह ब्यूरो बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के तहत कार्य करेगा। बयान में कहा गया है कि ब्यूरो जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा से संबंधित नियामक एवं निगरानी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा। बयान के अनुसार, 'ब्यूरो का नेतृत्व एक आईपीएस अधिकारी करेगा। एक वर्ष के लिए जहाजरानी (डीजीएस/डीजीएम) के महानिदेशक बीओपीएस के महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे।' बयान में कहा गया है, 'बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो सुरक्षा से संबंधित जानकारी का समय पर विश्लेषण, संग्रहण और आदान-प्रदान सुनिश्चित करेगा। यह साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा।

अमित शाह ने बंदरगाहों और जहाजों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित निकाय के गठन के संबंध में बैठक बुलाई, जिसमें बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी उपस्थित हुए। *बयान* में कहा गया है, 'बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो सुरक्षा से संबंधित जानकारी का समय पर विश्लेषण, संग्रहण और आदान-प्रदान सुनिश्चित करेगा।

गश्ती पोत 'अमूल्य' को भारतीय तटरक्षक बल में किया गया शामिल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के तेज गति वाले गश्ती पोत 'अमूल्य' को भारतीय तटरक्षक बल (आइसीजी) में शामिल कर लिया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक 'अमूल्य' निगरानी, खोज एवं बचाव, तस्करी विरोधी अभियान और प्रदूषण निवारण सहित कई प्रकार के मिशनों को अंजाम देगा, जिससे देश के पूर्वी तट की सुरक्षा में भारतीय तटरक्षक बल की भूमिका को मजबूती मिलेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 'अमूल्य' सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने तथा राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने की आइसीजी की इच्छा और प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

अधिकारी ने कहा, 'गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित यह 51 मीटर लंबा एफपीवी स्वदेशी जहाज निर्माण में एक नया मानदंड स्थापित करता है।' अधिकारियों ने कहा कि 60 फीसद से अधिक स्वदेशी उपकरणों से युक्त गश्ती पोत अमूल्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की निरंतर प्रगति को रेखांकित करता है।

'सहयोग के नए क्षेत्रों के उभरने से भारत और नीदरलैंड संबंध और प्रगाढ़ होंगे'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि द्विपक्षीय सहयोग के नए और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उभरने से भारत-नीदरलैंड संबंधों में और मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर, डिजिटल, साइबरस्पेस या जीवन विज्ञान के क्षेत्र में दोनों देश अधिक निकटता से काम करेंगे।

नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन वील के साथ वार्ता से पहले अपने प्रारंभिक संबोधन में जयशंकर ने यह भी कहा, 'हम आपके समर्थन पर भी भरोसा करते हैं, क्योंकि हम मुक्त व्यापार समझौते पर यूरोपीय संघ के साथ अपनी बातचीत के एक निर्णायक चरण की ओर बढ़ रहे हैं।' विदेश मंत्रालय ने बताया कि नीदरलैंड के विदेश मंत्री 17 से 19 दिसंबर तक भारत दौरे पर हैं।

एस जयशंकर

जयशंकर ने कहा, 'हम नीदरलैंड के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं- द्विपक्षीय रूप से और यूरोपीय संघ में एक प्रमुख भागीदार के रूप में भी। भारत और नीदरलैंड के बीच जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी है, एवं कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा जहाजरानी क्षेत्रों में बहुत मजबूत सहयोग है। विदेश मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर समेत सहयोग के नए क्षेत्रों के उभरने के साथ, मुझे लगता है कि हमारे संबंधों के और प्रगाढ़ होने की गुंजाइश है। इसलिए चाहे वह सेमीकंडक्टर हो, डिजिटल क्षेत्र हो, साइबरस्पेस हो या जीवन विज्ञान हो, हम आपके साथ और अधिक निकटता से काम करना चाहेंगे।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की पहल | सेहत | शुरू हुआ राष्ट्रीय अध्ययन 'उन्नति', जन्म से दो वर्ष तक के बच्चों का होगा आंकलन

स्वस्थ शिशु पहचान के लिए बनेगा स्वदेशी मानक आधार

राकेश शर्मा
नई दिल्ली, 19 दिसंबर

भारत में पैदा हो रहे शिशु के स्वस्थ होने की पहचान के लिए जल्द स्वदेशी आधार तय होंगे। नए मानक तय करने के लिए जन्म से दो वर्ष तक बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास के आकलन किया जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) की पहल पर 'भारतीय बाल विकास मानक अनुसंधान पहल' के अंतर्गत 'उन्नति' (भारतीय बच्चों के विकास एवं वृद्धि आकलन के मानकों का उन्नयन) नामक राष्ट्रीय अध्ययन शुरू हुआ है।

मौजूदा समय में बच्चों के सामाजिक व मानसिक वृद्धि और विकास के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बनाए गए मानक को आधार बनाया जाता है। जो करीब दो दशक पहले बनाए गए थे। तब से शिशु पोषण, स्तनपान की अवधि, पूरक आहार तथा पालन-पोषण से जुड़ी वैज्ञानिक समझ में काफी बदलाव आए हैं। नए मानक पूरी तरह से भारतीय भौगोलिक आधार पर रहेगा। इसके साथ ही भारतीय बच्चों में पतला शरीर लेकिन अधिक वसा की प्रवृत्ति, बढ़ता मोटापा और चयापचय संबंधी रोगों का खतरा भी एक बड़ी चुनौती है। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर आइसीएमआर ने विशेषज्ञों के साथ इस दिशा में काम शुरू किया। यह अध्ययन पूरे देश में छह केंद्र पर होगा।

दिल्ली से होगा उत्तर भारत के लिए अध्ययन

दिल्ली केंद्र में 'सोसाइटी फार एप्लाइड स्टडीज' के विशेषज्ञ डाक्टर सुनीता तनेजा, डाक्टर हरीश चेलानी सहित अन्य विशेषज्ञ बच्चों की पहचान करेंगे। डाक्टर हरीश चेलानी का कहना है कि चयन के लिए तय किया गया है कि ऐसे परिवार को चुने जिनकी मासिक आय दो लाख या इससे अधिक हैं। इसके अलावा माता-पिता में कोई रोग न हो, बच्चे को विकास के लिए उचित व्यवस्था मिली हो। प्रसव के बाद बच्चा 48 घंटे से अधिक समय तक नर्सरी में न रहा हो। मां द्वारा बच्चे को जन्म के बाद कम से कम छह माह तक सही तरीके से स्तनपान कराना और उसके बाद उचित पूरक आहार देना भी अनिवार्य शर्त होगी।

अध्ययन में 300 से 600 शिशु होंगे शामिल

अध्ययन में 300 से 600 शिशुओं (लड़का-लड़की दोनों) को शामिल किया जाएगा। इनके लिए करीब एक से दो हजार गर्भवती महिलाओं का नामांकन किया जाएगा। अध्ययन करीब साढ़े तीन साल तक चलेगा। इससे बच्चों के विकास के आकलन के लिए वैज्ञानिक और देश-उपयुक्त मानक मिलेंगे।

बनाए गए हैं अध्ययन केंद्र : अध्ययन के लिए दिल्ली, पुणे, शिलांग, पुरुलिया, बेंगलुरु और इंदौर को केंद्र बनाया गया है। यहां गर्भवती महिलाओं का चयन किया जाएगा। चयन के दौरान देखा जाएगा कि गर्भावस्था के 20 सप्ताह से पहले वह जांच करवा चुकी हो। 37 सप्ताह से कम गर्भावस्था अवधि वाली और चयनित क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की जांच की जाएगी। उन्हें संतुलित आहार, शारीरिक सक्रियता, नियमित जांच, स्तनपान और शिशु देखभाल के महत्व के बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही सकारात्मक सोच और दैनिक तनाव से निपटने के लिए मानसिक परामर्श भी दिया जाएगा।

Jansatta Page No-10

भारत मंडपम में पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन के समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा

विश्वसनीय नियामकीय ढांचा विकसित करने की जरूरत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा को वर्तमान के साथ भविष्य की जरूरत पर ध्यान देना होगा। यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। शुक्रवार को भारत मंडपम में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक सम्मेलन के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि जब परंपरा और प्रौद्योगिकी साथ आते हैं, तो वैश्विक स्वास्थ्य को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

आयुर्वेद संतुलन को स्वास्थ्य के बराबर मानता है लेकिन आज मधुमेह, दिल का दौरा, तनाव से लेकर कैंसर तक की बीमारियों के पीछे जीवन शैली और असंतुलन मुख्य कारण है। इनके पीछे असंतुलित कार्य शैली, भोजन, नींद सहित अन्य है।

इस सम्मेलन में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने, नियमों को आसान बनाने और प्रशिक्षण व ज्ञान साझा करने के लिए नए रास्ते खुले हैं। ऐसा सहयोग भविष्य में पारंपरिक चिकित्सा को सुरक्षित और अधिक भरोसेमंद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि जामनगर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए डब्ल्यूएचओ वैश्विक केंद्र की स्थापना हुई है। आज कुछ खास हस्तियों को प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक, डाक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस के साथ दिल्ली में डब्ल्यूएचओ के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। मोदी ने योग प्रशिक्षण पर डब्ल्यूएचओ की तकनीकी रपट और 'फ्राम रूट्स टू ग्लोबल रीचः 11 इयर्स आफ ट्रांसफार्मेशन इन आयुष' नामक पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने आयुष मार्क का भी अनावरण किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

दूसरे विश्व चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह के दौरान मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस, जेपी नड्डा व अन्य।

अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट जारी

प्रधानमंत्री ने अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। कोरोना महामारी के बाद अश्वगंधा की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ी और कई देशों में इसका इस्तेमाल होने लगा। भारत अपने शोध और सबूत-आधारित सत्यापन के माध्यम से अश्वगंधा को एक विश्वसनीय तरीके से आगे बढ़ा रहा है। आज दुनियाभर में पारंपरिक दवाओं को लेकर सोच तेजी से बदल रही है। ये दवाएं गंभीर स्थितियों में भी असरदार भूमिका निभा सकती हैं।

भारत ने दिखाया कि परंपरा और विज्ञान साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं: टेड्रोस

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक डा टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने शुक्रवार को कहा कि स्वास्थ्य सेवा एकीकृत और समावेशी होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान और परंपरा एक-दूसरे के पूरक हैं। वह पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर बोल रहे थे। भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से आयोजित यह शिखर सम्मेलन बुधवार को शुरू हुआ था और इसमें 100 से अधिक देशों के मंत्री, वैज्ञानिक, नेता तथा विशेषज्ञ शामिल हुए। भारत की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने यह साबित कर दिया है कि परंपरा और नवाचार साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं।

Jansatta Page No-10

मंथन

जन-केंद्रित स्वास्थ्य की पहल

बढ़ते हुए गैर-संचारी रोगों, बढ़ती वृद्ध जनसंख्या और अधिक समावेशी स्वास्थ्य माडल की वैश्विक मांग ने एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में नवाचार की राह खोली है

वैद्य राजेश कोटेचा
सचिव, आयुष मंत्रालय

दुनिया भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उन दृष्टिकोणों की खोज में हैं, जो निवारक, जन-केंद्रित, सतत और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक हों। यह बदलाव कोई प्रवृत्ति नहीं, बल्कि एक जरूरत है, जिसे बढ़ते हुए गैर-संचारी रोगों, बढ़ती वृद्ध जनसंख्या और अधिक समावेशी स्वास्थ्य माडल की वैश्विक मांग ने आकार दिया है। इसी पृष्ठभूमि में भारत में एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में नवाचार उभर कर सामने आए हैं। परंपरागत ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ समन्वित करते हुए हम ऐसे स्वास्थ्य माडल विकसित कर रहे हैं, जो प्रमाण-आधारित होने के साथ-साथ समुदायों के कुशल-क्षेम में गहराई से निहित हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुदृढ़ हुआ है। उन्होंने हमेशा समग्र, निवारक और लोक-केंद्रित स्वास्थ्य दृष्टिकोण का समर्थन किया है। भारत की इस पहल की मुख्य शक्ति शोध, नैदानिक अध्ययन और जन स्वास्थ्य के एकीकरण में निहित है।

देश भर में विभिन्न एम्स संस्थानों में स्थापित आयुष-आइसीएमआर उन्नत एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र इस व्यवस्थागत सहयोग की दिशा में एक निर्णायक कदम हैं। ये केंद्र गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, जेरियाट्रिक देखभाल और कैंसर पर केंद्रित हैं, और चिकित्सकों, बायोमेडिकल विज्ञानियों और पारंपरिक चिकित्सा विशेषज्ञों को एक साझा मंच पर लेकर आ रहे हैं।

वैज्ञानिक और सामाजिक रूप से पारंपरिक चिकित्सा की और अधिक मजबूत होती वैश्विक मान्यता के लिए अगस्त 2023 एक ऐतिहासिक क्षण था, जब भारत ने गुजरात के गांधीनगर में प्रथम डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यह आयोजन जी20 स्वास्थ्य मंत्रीस्तरीय बैठक के साथ आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन ने विभिन्न क्षेत्रों के नीति निर्धारकों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और समुदाय के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे के साथ जोड़ने का कार्य किया। इसने राजनीतिक प्रतिबद्धता को मजबूत किया, डाटा-आधारित कार्यवाही को बढ़ावा दिया और उत्तरदायी, प्रमाण-आधारित एकीकरण की नींव रखी। जैव-विविधता संरक्षण, समान लाभ साझा करने, डिजिटल नवाचार और सार्वभौमिक पहुंच की मांग करने वाला गुजरात घोषणा-पत्र इस वैश्विक संवाद में एक महत्वपूर्ण बदलाव वाले बिंदु के रूप में सामने आया।

प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना और दूरदृष्टि के अनुरूप यह ऐतिहासिक उपलब्धि-पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति के केंद्र में लाने की भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाती है। इसी प्रवाह की क्षमता को आधार बनाते हुए भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने द्वितीय डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया। ''रिस्टोरिंग बैलेंस- द साइंस एंड प्रैक्टिस आफ हेल्थ एंड वेल बिंग'' थीम से प्रेरित यह शिखर सम्मेलन डब्ल्यूएचओ की 10-वर्षीय वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति (2025–2034) को आगे बढ़ाएगा। यह नीति-निर्माताओं, विज्ञानियों, उद्योग नेताओं, नवाचारकर्ताओं और समुदाय के प्रतिनिधियों को एकीकृत, न्यायसंगत और सतत स्वास्थ्य प्रणाली की साझा दृष्टि गढ़ने के लिए एक मंच पर लेकर आएगा। इसी एकीकृत दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण कैंसर देखभाल है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआइआइए) के एकीकृत आंकोलाजी केंद्र ने अब तक लगभग 8,000 मरीजों को प्रमाण-आधारित, व्यक्तिगत देखभाल प्रदान की है, जो मुख्यधारा के उपचार का पूरक है।

यह परिवर्तन जन स्वास्थ्य में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के माध्यम से आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) महत्वपूर्ण प्राथमिक वेलनेस केंद्रों के रूप में उभरे हैं, जिनके लाभार्थियों की संख्या 2021 के पांच करोड़ से बढ़कर 2024 में 11.5 करोड़ हो गई। डीजीएचएस के अंतर्गत आयुष वर्टिकल ने संस्थागत शासन को मजबूत किया, मानक उपचार दिशानिर्देश विकसित किए और समकालीन चुनौतियों का समाधान करने वाली जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किए हैं। 3,800 से अधिक अस्पतालों, 37,000 औषधालयों और 39 देशों में 43 आयुष सूचना केंद्रों के साथ, भारत ने विश्व की सबसे मजबूत पारंपरिक चिकित्सा अवसंरचनाओं में से एक स्थापित की है। भारत का अनुभव दर्शाता है कि एकीकृत स्वास्थ्य केवल समानांतर प्रणालियों के बारे में नहीं, बल्कि विज्ञान सम्मत संभावनाओं के विस्तार और मरीजों की सुचित विकल्प प्रदान करने के बारे में है।

द्वितीय डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ आयोजित। संयुक्त राष्ट्र

Dainik Jagaran Page No-9

हजार चेहरे हैं मौजूद आदमी गाएब
ये किस खराबे में दुनिया ने ला कर छोड़ दिया है।
-शहजाद अहमद

दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का विश्व रिकार्ड जिन्होंने बनाया, आज उनका एक वीडियो पूरी दुनिया में घूम रहा है। उस वीडियो को एक हादसा मान लिया जा सकता था, अगर सत्ता पक्ष से जुड़ा समुदाय उसे न्यायोचित बता कर हादसों का अकीर्तिमान नहीं खड़ा करता। जिस तरह के व्यवहार को स्कूल, कालेज, दफ्तर में उत्पीड़न माना जाता है, उसे सत्ता-समुदाय इसलिए न्यायोचित ठहरा रहा है, क्योंकि पीड़ित पक्ष के साथ 'हिजाब' जुड़ा हुआ है। नफरत की राजनीति स्त्री अस्मिता का भी विभाजन कर रही है। उदाहरण दिया जा रहा है अशोक गहलोत का। अगर कांग्रेस के कथित गलत काम आपके लिए कीर्तिमान हैं तो इस पार्टी के खिलाफ दिन-रात नफरत क्यों उंड़ेली जाती है? बिहार में हाल में हुई नारी अस्मिता की हार का विश्लेषण करता बेबाक बोल।

बेबाक बोल

बिहार

मुकेश भारद्वाज

बिहार...विधानसभा चुनाव शुरू होने के पहले से इस स्तंभ में बिहार की चर्चा लगातार हो रही है। अतीत के बोझ से दबे विश्लेषक कह रहे थे, बिहार का चुनाव देश को दिशा देगा। चुनाव के दौरान ही जिस तरह वोट पाने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया गया, उसी समय अहसास हो गया था, यह चुनाव बहुत ही गलत राजनीतिक दिशा देगा।

चुनावी नतीजों के बाद विश्लेषकों ने दिल के खुश रखने को ख्याल अच्छा है की मिसाल देते हुए चुनाव विश्लेषण का सारा जोर महिला मतदाताओं पर लगा दिया। महिलाओं के खाते में दस हजार रुपए डाल कर, लोकतांत्रिक अनैतिकता को मातृ-शक्ति के नाम कर दिया गया। इसका भावार्थ यही है कि स्त्री मतदाता के लिए लोकतांत्रिक तकाजा कोई मायने नहीं रखता। इस स्त्री-विमर्श पर सवाल तभी उठे थे जब बिहार विधानसभा के नवगठित मंत्रिमंडल में महज दस फीसद महिलाओं को जगह दी गई थी।

विधानसभा चुनाव के बाद बिहार लगातार ऐसी दिशा में चलता दिख रहा है, जिस पर शायद ही देश चलना चाहे। बिहार की संपूर्ण क्रांति वाली राजनीतिक विरासत आज एक ऐसी भ्रांति में बदल गई है, जहां सदन और सड़क के व्यवहार में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। ताजा मामला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयुष चिकित्सक का नियुक्ति-पत्र लेने आई महिला का हिजाब हटाने की कोशिश का। इस घटना का वीडियो जितनी बार भी आंखों से गुजरता है, एक दहशत सी हो जाती है।

हालांकि, नीतीश कुमार का इस तरह का यह कोई अकेला वीडियो नहीं है। एक खास समय के बाद वे स्त्री-मुद्दे पर लगातार अमर्यादित से दिखे हैं। वह वीडियो अब भी इंटरनेट पर मौजूद है, जब विधानसभा में परिवार नियोजन पर बात करने के दौरान वे स्त्री गरिमा का हनन करने लगे। उस वक्त राजद के साथ गठबंधन की सरकार थी तो 'मां के सम्मान में, भाजपा मैदान में' जैसी स्थिति होनी ही थी। इसके बाद भी स्त्री मुद्दे पर नीतीश कुमार का असहज व्यवहार बार-बार दिखता रहा। विधानसभा वाले मुद्दे पर तब महागठबंधन से जुड़े बौद्धिक इसे खुलापन तक बताने को तैयार हो गए थे, कि ऐसे बोले बिना काम कैसे चलेगा। और, आज राजग का पक्ष जिस तरह से इस अनैतिक कर्म का बचाव कर रहा है, वह भी एक इतिहास बना रहा है।

फिलहाल, सार्वजनिक रूप से हम नीतीश कुमार की चिकित्सकीय स्थिति के संदर्भ में कुछ भी नहीं जानते हैं, और न जानने दिया जाएगा। हम बस इतना अनुमान लगा सकते हैं कि बुजुर्ग-अवस्था में खास चिकित्सकीय मामलों में कोई इंसान अपने व्यवहार पर से अपना नियंत्रण खो सकता है।

आज के समय में हमारी चिंता नीतीश कुमार नहीं हैं। हमारी चिंता में वे लोग हैं, जिनके राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस हालत में नीतीश कुमार, दसवीं बार मुख्यमंत्री बनने का विश्व रिकार्ड बना पाए। वे बिहार की अगुआई के लिए सुयोग्य हैं कि नहीं, यह मायने नहीं रखता था। मायने रखता था सिर्फ उनके जरिए हासिल होने वाला वोट बैंक।

हमारी चिंता उन लोगों की चुप्पी है, जो उनकी बीमारी के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, और इस बहाने अपनी बीमार मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद वही लोग इस तरह के और वीडियो आने का इंतजार कर रहे हैं। चिकित्सा के संदर्भ में बात करने के बजाय चुपचाप ऐसे वीडियो आने का इंतजार क्यों हो रहा है, इसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है।

हमारी चिंता वे लोग हैं जो इस घटना को सिर्फ इसलिए न्यायोचित ठहरा रहे हैं कि पीड़ित स्त्री हिजाब पहनने वाले समुदाय से है। समाजवादी मूल्यों का दावा करने वाली पार्टी के एक नेता ने तो इतना घृणित बयान दे दिया है कि उसे इस स्तंभ में लिखा नहीं जा सकता। लेकिन वह स्त्री विरोधी बयान अखबारों की सुर्खियों का हिस्सा है, टीवी पर बहस चल रही है, और उस बयान को बोल कर सत्ता समर्थक अट्टहास कर रहे हैं। वहीं भाजपा के गिरिराज सिंह भी बिहार की जमीन से विश्व रिकार्ड बनाने में लगे हैं। इस रिकार्ड के लिए उनके बयानों के प्रतिद्वंद्वी भी उनके बयान ही होंगे कि लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से सबसे खराब कौन सा है।

सोचिए, यह घटना कहां हुई है? यह घटना बिहार में हुई है। जहां अशिक्षा, बेरोजगारी के कारण स्त्री की हैसियत इतनी कमजोर है कि स्त्री को हिंसा से बचाने के लिए शराबबंदी की गई। दावा किया जाता है कि शराबबंदी की सबसे बड़ी समर्थक वे स्त्रियां हैं जो शराब के कारण हिंसा की शिकार होती हैं। जो सत्ता समर्थक स्त्री सुरक्षा के नाम पर शराबबंदी का समर्थन कर रहे थे, वे आज इस घटना का भी समर्थन कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं के समर्थन से आगे जिस तरह की अराजक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्या हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं?

कल को सड़क पर कोई भी किसी स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, और उसके बाद सड़क पर ही इंसाफ भी होगा कि स्त्री घूंघट वाली थी या बुर्के वाली। न्याय मर्दों की संख्या के हिसाब से तय होगा कि वे किस तरह की विचारधारा का समर्थन करते हैं। आज, घर से बाहर काम की जगह पर या दफ्तर में किसी स्त्री के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो यह यौन उत्पीड़न के दायरे में आ सकता है। कार्यस्थल की अंदरूनी कार्रवाई से असंतुष्ट स्त्री अदालत जा सकती है। आज के सत्ता समर्थक कल कार्यस्थलों में इस तरह का न्याय मांगने की कोशिश करने वाली हर स्त्री के इंसाफ मांगने पर कह सकते हैं कि या तो नौकरी छोड़ो या नर्क में जाओ।

नीतीश कुमार के संदर्भ में खास अवधि को छोड़ दें तो वे राजनीति में बहुत हद तक नैतिकता की मिसाल थे। इस घटना के बाद भी अगर व्यवस्था द्वारा माफी मांग ली गई होती तो बात कुछ और थी। लेकिन माफी मांगने के बजाय पूरे मामले पर नफरत की राजनीति का वर्चस्व हो गया। एक स्त्री की गरिमा का हनन कर सत्ता पक्ष व उसके समर्थकों ने अपनी गरिमा जिस तरह से गिराई है, उसके दूरगामी परिणाम संसद से सड़क तक दिखेंगे।

वैसे, स्त्री समुदाय को अपनी उम्मीद सत्ता पक्ष के ही एक और व्यक्ति की तरफ मोड़ लेनी चाहिए। वे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को तो हर दोहरे इंजन वाली सरकार अपने राज्य का प्रतीक निशान बना रही है। बिहार में भी चुनाव नतीजों के बाद 'बुलडोजर बाबा' की धूम मच चुकी है। बुर्का विवाद में जिस तरह सत्ताधारी दल के नेता व समर्थक सड़क छाप 'रोमियो' की भाषा बोल रहे हैं, अब उधर से ही कुछ सुधार की उम्मीद है। शायद योगी का 'एंटी रोमियो' दस्ता ही इनमें सुधार ला पाए।

जब सदन के प्रतिनिधि सड़क जैसा व्यवहार करने लगेंगे और पूरा सत्ता समुदाय या तो उसे न्यायोचित ठहराए या चुप्पी साध ले तो, इस सन्नाटे के खिलाफ चीखने का वक्त आ गया है। आर्थिक संदर्भ में बिहार को बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसे अभी तक वह अपने राजनीतिक अभिमान से छिपाता था।

विरासत का मिला तो सब खर्च कर चुका है बिहार। आगे उसके पास कौन सी राजनीतिक जमा-पूंजी रह जाएगी। 'नर्क में जाओ' जैसा अहंकार?

Jansatta Page No-7

अराजकता के पांव

बांग्लादेश में अराजकता फिर से अपने पांव पसारने लगी है। हाल ही में वहां एक प्रमुख नेता की गोली मारकर हत्या कर देने के बाद शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों से कई जगह हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच अल्पसंख्यकों खासकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर भी खतरा पैदा हो गया है। वहां गुरुवार को ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति की पीटकर हत्या कर दी गई और उसके शव को आग लगा दी गई। इससे स्पष्ट है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का विरोध करने वालों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। सवाल है कि वहां अंतरिम सरकार का जिस मकसद से गठन किया गया था, क्या वह चरमपंथियों के दबाव में अपना उद्देश्य भूल गई है? आखिर क्या वजह है कि वहां न तो कानून व्यवस्था दुरुस्त हो पा रही है और न ही लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनने का मार्ग प्रशस्त हो पा रहा है? अस्थिरता और हिंसा के इस माहौल में बांग्लादेश-भारत के संबंध भी लगातार चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं।

बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी नामक जिस नेता की गोली मारकर हत्या की गई, वह जुलाई में सरकार के विरुद्ध हुए प्रदर्शनों में प्रमुख चेहरा थे। सरकार की ओर से गुरुवार को उनकी मौत की पुष्टि किए जाने के बाद कई जगह हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ लोगों ने भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर भी ईंट और पत्थरों से हमला किया। इससे पहले बांग्लादेश के कुछ राजनेताओं ने जिस तरह भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए, उसका सीधा असर भारत के साथ उसके संबंधों पर पड़ा है। बांग्लादेश में सुरक्षा का माहौल जिस तेजी से बिगड़ रहा है और पहले भी पूर्वोत्तर भारत के कुछ अलगाववादी समूहों ने बांग्लादेश में शरण ली है, उसके मद्देनजर भारत की चिंता स्वाभाविक है। फिलहाल बांग्लादेश में जिस तरह की अराजकता फैली हुई है और उसकी आंच में बहुत कुछ झुलसने की आशंका है, उसे देखते हुए भारत सरकार को चाहिए कि वह कूटनीतिक स्तर पर इन मसलों को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के समक्ष प्रभावी तरीके से उठाए।

Jansatta Page No-6

पूर्वी समुद्री तट की सुरक्षा की मजबूती को आइसीजी को मिला अमूल्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- तटरक्षक बल की समुद्री निगरानी, खोज और बचाव, तस्करी विरोधी अभियान सहित कई मिशनों के लिए होगा अहम
- नई अदम्य श्रेणी की आठ गश्ती पोतों की शृंखला के तहत तीसरा पोत है 'अमूल्य'

'अमूल्य' जहाज के कमीशनिंग के दौरान भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों के साथ अमिताभ प्रसाद, रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव। प्रेट

भारतीय तटरक्षक बल (आइसीजी) को नई पीढ़ी का तीव्र गति वाला गश्ती पोत 'अमूल्य' मिल गया है। नई अदम्य श्रेणी की आठ तीव्र गश्ती पोतों की शृंखला में अमूल्य भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल होने वाला तीसरा पोत है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित और निर्मित 51 मीटर लंबा यह एफपीवी (तीव्र गश्ती पोत) देश में पोत निर्माण में नया मानदंड स्थापित करता है। इसके 60%से अधिक घटक देश में निर्मित हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार अमूल्य अर्थात अनमोल आत्मनिर्भर भारत और मेक-इन-इंडिया पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में भारत की निरंतर प्रगति को दर्शाता है।

गोवा में एक समारोह के दौरान शुक्रवार को इसे तटरक्षक बल में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया। अमूल्य समुद्र में निगरानी, खोज और बचाव, तस्करी विरोधी अभियान और प्रदूषण नियंत्रण सहित कई मिशनों को अंजाम देने के साथ ही देश के पूर्वी समुद्री तट की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाएगा। यह पोत बेहतर गतिशीलता, संचालन अनुकूलता और समुद्र में उन्नत प्रदर्शन करने में सक्षम है। अमूल्य को तटरक्षक बल में शामिल किए जाने के समारोह की अध्यक्षता रक्षा विभाग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने की और इसमें तटरक्षक बल, केंद्र, राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। अमूल्य ओडिशा के पारादीप में तैनात रहेगा और तटरक्षक क्षेत्र (उत्तर पूर्व) कमान के प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण में काम करेगा। इस पोत की कमान कमांडेंट अनुपम सिंह को सौंपी गई है जिसमें पांच अधिकारी और 34 कर्मी शामिल हैं।

अमूल्य की खूबियां

- 3000 किलोवाट के दो उन्नत डीजल इंजनों से संचालित यह पोत 27 समुद्री मील की अधिकतम गति से चल सकता है।
- इसकी परिचालन क्षमता 1500 समुद्री मील की है। इससे भारत के समुद्री क्षेत्रों में लंबे अभियान को अंजाम देना संभव हो पाएगा।
- आधुनिक डिजाइन पद्धति पर आधारित यह पोत दक्षता, स्थायित्व और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता से युक्त है।
- समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए यह पोत स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक हथियारों-प्रणालियों से सुसज्जित है
- यह 30 मिमी सीआरएन-91 तोप और दो 12.7 मिमी रिमोट-कंट्रोल तोप, आग नियंत्रण प्रणालियों, एकीकृत मशीनरी नियंत्रण प्रणाली से लैस है।

Dainik Jagaran Page No-5

भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा 'शांति' विधेयक

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और 2047 के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लाया गया सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट आफ न्यूक्लियर एनर्जी फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया (शांति) विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। यह विधेयक परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम के प्रविधान को सुव्यवस्थित करता है। आइये जानते हैं यह भारत को परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने में कैसे मदद कर सकता है?

बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं परमाणु ऊर्जा

परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कैंसर के इलाज, कृषि और उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में भी उपयोगी है। यह विधेयक नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ डाटा प्रोसेसिंग, स्वास्थ्य सेवा और उद्योग जैसे क्षेत्रों से बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, खाद्य एवं कृषि, उद्योग एवं अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में परमाणु एवं विकिरण प्रौद्योगिकियों के उपयोग को नियमन के दायरे में लाना है, जबकि अनुसंधान, विकास एवं नवाचार गतिविधियों को लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट प्रदान करना है।

परमाणु क्षेत्र में निजीकरण को मिलेगा बढ़ावा

यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक हित से समझौता किए बिना 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार निजी और संयुक्त उद्यम भागीदारी को सक्षम बनाता है। यह विधेयक परमाणु क्षेत्र को शर्तों के तहत निजीकरण के लिए खोलता है, जो स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के बाद आया है। हालांकि, निर्धारित सीमा से अधिक यूरेनियम खनन का अधिकार पूरी तरह से सरकार के पास ही रहेगा। इसके साथ ही प्रयुक्त ईंधन के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी सरकार के पास रहेगी। खनन सामग्री, विखंडनीय सामग्री और भारी जल जैसी रणनीतिक सामग्री पर सरकार का कड़ा नियंत्रण बना रहेगा।

कठोर सुरक्षा मानक

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा, परमाणु सुरक्षा मानक अपरिवर्तित व अडिग हैं, जो 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम में निहित कड़े सिद्धांतों द्वारा संचालित हैं। सिद्धांत सुरक्षा पहले, उत्पादन बाद में पर जोर देता है। सुरक्षा मानकों में कठोर निरीक्षण की व्यवस्था है, जिसमें निर्माण के दौरान त्रैमासिक निरीक्षण, संचालन के दौरान द्विवार्षिक निरीक्षण, पांच-वार्षिक लाइसेंस नवीनीकरण व अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप निगरानी शामिल है। भारत के परमाणु संयंत्र भौगोलिक रूप से भूकंपीय फाल्ट क्षेत्रों से दूर हैं, जिससे भारतीय रिएक्टरों में विकिरण का स्तर तय वैश्विक सुरक्षा सीमाओं से कई गुना कम है।

तय होगी जवाबदेही

विधेयक में परमाणु क्षति के लिए संशोधित एवं व्यावहारिक नागरिक दायित्व ढांचा प्रस्तावित किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा दिया गया है और सुरक्षा उपायों, गुणवत्ता आश्वासन व आपातकालीन तैयारियों से संबंधित तंत्रों को सुदृढ़ किया गया है। इसमें परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद सहित नई संस्थागत निर्माण, दावा आयुक्तों की नियुक्ति, परमाणु क्षति से जुड़े मामलों के लिए दावा आयोग का प्रविधान है, जिसमें विद्युत अपील न्यायाधिकरण अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। प्रस्तावित कानून परमाणु ऊर्जा के विस्तार को सुरक्षा, जवाबदेही व जनहित संग संतुलित करने का प्रयास करता है, जिससे परमाणु ऊर्जा को सुरक्षा व कम कार्बन वाले भविष्य की दिशा में व्यापक राष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत रखा जा सके।

स्रोत : आइएएनएस

****

Dainik Jagaran Page No-3

राजगीर महोत्सव का भव्य आगाज

राजगीर (एसएनबी)। राजगीर के वैभारगिरी पर्वत की तलहटी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में शुक्रवार से तीन दिवसीय राजगीर महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। महोत्सव का उद्घाटन ग्रामीण विकास सह परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता

महोत्सव में दिखा संस्कृति-विकास का संगम

ग्रामीण विकास सह परिवहन मंत्री ने किया उद्घाटन, पर्यटन मंत्री ने की अध्यक्षता

पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने की।

पर्यटन मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राजगीर कई धर्मों का संगम स्थल है और यहां हर वर्ष बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। उन्होंने बताया कि राजगीर में करीब 20 प्रकार की विकास योजनाएं संचालित हैं, जिनमें ब्रह्मकुंड योजना, जू सफारी और नेचर सफारी प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजगीर को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

राजगीर महोत्सव का शुभारंभ करते मंत्री श्रवण कुमार, अरुण शंकर प्रसाद व अन्य।

सर्वधर्म प्रार्थना मे शामिल बौद्ध भिक्षु व अन्य।

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राजगीर महोत्सव का इतिहास समृद्ध रहा है और इसकी पहाड़ियां हिमालय से भी प्राचीन मानी जाती है। यह महोत्सव स्थानीय संस्कृति और विशिष्टताओं को जानने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार द्वारा रोजगार सृजन के लिए एक करोड़ 56 लाख परिवारों को सहायता दी गई है तथा जीविका के माध्यम से 11 लाख स्वयं सहायता समूह गठित कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।महोत्सव की शुरुआत सर्वधर्म मंगलाचरण से हुई, जिसमें सनातन, बौद्ध, जैन, सिख और मुस्लिम सहित विभिन्न धर्मों के अनुयायियों ने मंगलपाठ किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बॉलीवुड गायक कैलाश खेर ने अपनी सुरीली आवाज से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शक कार्यक्रम का आनंद लेते नजर आए।मौके पर कई विभागों के स्टॉल लगाए गए है, जहां आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम में विधायक, विधान पार्षद, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डीडीसी श्रीकांत कुंडली खांडेकर ने किया।

Rashtriya Sahara Page No-10

चीन के बाद नीदरलैंड्स पाकिस्तान का बड़ा हथियार सप्लायर, भारत ने उठाया मुद्दा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- विदेश मंत्री जयशंकर ने नीदरलैंड्स के अपने समकक्ष के साथ वार्ता में जताई चिंता
- सेमीकंडक्टर, साइबरस्पेस, जीवन विज्ञान के क्षेत्र में मिलकर काम करने की उम्मीद जताई

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन वील के साथ अपनी बैठक में पाकिस्तान को नीदरलैंड्स से हो रही हथियारों की आपूर्ति का मुद्दा उठाया। भारतीय पक्ष ने इस पर गंभीर चिंता जताई, क्योंकि पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक देश माना जाता है। वैन वील ने बाद में भारतीय मीडिया से बातचीत में इसकी पुष्टि की और कहा कि यह आपूर्ति पुराने समझौतों के तहत हो रही है, जिन्हें पूरा किया जाना आवश्यक है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच तेजी से संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं लेकिन नीदरलैंड्स की तरफ से पाकिस्तान को लगातार हथियारों की आपूर्ति भारत के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। नीदरलैंड्स आज की तारीख में चीन के बाद पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान को सैन्य जहाजों, हेलीकाप्टर और राडार की आपूर्ति नीदरलैंड्स करता है। बैठक में

नई दिल्ली में शुक्रवार को नीदरलैंड्स के अपने समकक्ष डेविड वैन वील के साथ चर्चा करते विदेश मंत्री एस जयशंकर। एएनआइ

दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच आर्थिक, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों पर जोर दिया और कहा कि दोनों देश जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और व्यापार में साझेदारी बढ़ा सकते हैं। जयशंकर ने कहा कि हम निश्चित रूप से नीदरलैंड्स के साथ अपने संबंधों को महत्व देते हैं, द्विपक्षीय रूप से तथा यूरोपीय संघ में एक प्रमुख भागीदार के रूप में। आज जब हम मिल रहे हैं, तो हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि पिछले कुछ महीनों में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जिन्होंने हमारे सहयोग में नए आयाम जोड़े हैं। जयशंकर ने कहा कि हम आपकी मदद पर भरोसा करते हैं क्योंकि हम यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत के एक निर्णायक चरण की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि यह चरण सफल होगा। हमारी जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी है लेकिन सेमीकंडक्टर जैसे नए सहयोग के क्षेत्रों में हमारे संबंधों को बढ़ाने की गुंजाइश है। इसलिए सेमीकंडक्टर, साइबरस्पेस क्षेत्र हो, हम और निकटता से काम करना चाहेंगे।

Dainik Jagaran Page No-3

2019 में केंद्र सरकार ने हर ग्रामीण घर में नल से जल देने के की योजना शुरू की थी। तब केवल 3.23 करोड़ (16.7 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल-जल कनेक्शन था। 15 दिसंबर 2025 तक, देश में अनुमानित 19.37 करोड़ ग्रामीण घरों में से 15.76 करोड़ (81.42 प्रतिशत) घरों को नल कनेक्शन दिए गए हैं।

आधुनिक कैंसर उपचार से जुड़ेंगी भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ के वैश्विक शिखर सम्मेलन में कही यह बात

आने वाले समय के लिए साझा रोडमैप के रूप में काम करेगा दिल्ली घोषणा-पत्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पारंपरिक चिकित्सा के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व भर के विशेषज्ञों के समक्ष इस बात को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुष मंत्रालय और जामनगर स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा केंद्र ने भारत में कैंसर के उपचार को लेकर नई पहल की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जो संयुक्त प्रयास किए गए हैं, उसके तहत पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक चिकित्सा कैंसर उपचार के साथ जोड़ा जाएगा। यह पहल साक्ष्य आधारित दिशा-निर्देश तैयार करने में भी सहायक होगी।

डब्ल्यूएचओ के पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजत वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन पर पीएम ने कहा कि तीन दिवसीय संवाद ने दिल्ली घोषणा-पत्र का मार्ग प्रशस्त किया है, जो आने वाले वर्षों के लिए एक साझा रोडमैप के रूप में कार्य करेगा।

नई दिल्ली में शुक्रवार को डब्ल्यूएचओ के वैश्विक सम्मेलन के समापन अवसर पर अश्वगंधा का स्मारक डाक टिकट जारी करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। एएनआइ

भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम के समापन सत्र में पीएम मोदी ने कहा, एक समय यह धारणा थी कि पारंपरिक चिकित्सा केवल स्वास्थ्य या जीवनशैली तक ही सीमित थी, पर अब यह धारणा बदल रही है। पारंपरिक चिकित्सा गंभीर परिस्थितियों में भी प्रभावी भूमिका निभा सकती है और भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले तीन दिनों में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व भर के विशेषज्ञों ने गंभीर और सार्थक चर्चाओं में भाग लिया। भारत इस उद्देश्य के लिए सशक्त मंच प्रदान कर रहा है और डब्ल्यूएचओ की सक्रिय भूमिका है।

मोदी ने कहा, यह भारत का सौभाग्य और गौरव का विषय है कि जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। याद दिलाया कि 2022 में पहले पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व ने भारत को इस जिम्मेदारी का पूर्ण विश्वास सौंपा था। यह सभी के लिए खुशी की बात है कि केंद्र की प्रतिष्ठा और प्रभाव वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण इस सम्मेलन की सफलता है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक पद्धतियों का संगम देखने को मिल रहा है। यहां कई नई पहलें शुरू की गई हैं, जो चिकित्सा विज्ञान और समग्र स्वास्थ्य के भविष्य को बदल सकती हैं। पीएम ने पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक पुस्तकालय के शुभारंभ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह वैश्विक मंच पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित वैज्ञानिक डाटा व नीतिगत दस्तावेजों को एक ही स्थान पर संरक्षित करेगा।

प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत विश्व भर में स्वास्थ्य संबंधी साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पहला सहयोग दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को कवर करने वाले बिम्सटेक देशों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना है और दूसरा सहयोग विज्ञान, पारंपरिक प्रथाओं और स्वास्थ्य को एकीकृत करने के उद्देश्य से जापान के साथ किया गया है।

उन्होंने आगाह किया कि 21वीं सदी में जीवन में संतुलन बनाए रखने की चुनौती और बड़ी होने वाली है। एआइ और रोबोटिक्स के साथ नए तकनीकी युग का आगमन मानव इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन है और आने वाले वर्षों में जीवनशैली में अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। ऐसे में पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा को न केवल वर्तमान जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि भविष्य की जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए। अश्वगंधा पर बढ़ते विश्वास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि भारत समय-परीक्षित जड़ी-बूटियों को वैश्विक जन स्वास्थ्य का हिस्सा बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस समारोह में मौजूद डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डा.टेड्रोस ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को समग्र व एकीकृत होना चाहिए। विज्ञान और परंपराएं एक-दूसरे की पूरक हैं।

Dainik Jagaran Page No-3

संसदीय कामकाज

मुद्दों ने खूब बढ़ाया ताप, पर शीतकालीन सत्र में काम नहीं ठिठका

19 दिन चले संसद सत्र में लोकसभा की 111 तो राज्यसभा की 121 प्रतिशत रही उत्पादकता, कई प्रमुख विधेयक संसद से पारित, विपक्ष के जबरदस्त विरोध के बावजूद वीबी-जी राम जी बिल पास, आरंभिक गतिरोध के बाद सदन को पटरी पर लाई वंदे मातरम् और चुनाव सुधारों पर महत्वपूर्ण चर्चा

जितेंद्र शर्मा • जागरण

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। 19 दिन तक चले सत्र में लोकसभा की 111 तो राज्यसभा की 121 प्रतिशत उत्पादकता रही। सियासी मुद्दों की गर्मी के बावजूद सत्र में एसआइआर विवाद के संदर्भ में 'चुनाव सुधार' पर चर्चा ने गतिरोध की स्थिति नहीं बनने दी। वहीं वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष चर्चा के बहाने भी सत्ता पक्ष-विपक्ष ने मोर्चा मजबूती से संभाले रखा। यही दो मुद्दे इतने अहम रहे कि सत्र पटरी पर आया और राजनीतिक ताप भी इन्हीं मुद्दों ने बढ़ाया, पर विधायी कार्य बाधित नहीं हुआ।

तकरार और सुलह की धूप-छांव में चले सत्र के दौरान सरकार कई विधेयक पारित कराने में सफल रही। सबसे अधिक विवाद मनरेगा की जगह लाया गया विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक (वीबी-जी राम जी) रहा। खास तौर पर कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस के जबर्दस्त विरोध के बाद भी सरकार ने इसे

संसद भवन। प्रतीकात्मक

पारित कराने में सफलता अवश्य पा ली,पर खाली हाथ विपक्ष भी नहीं रहा। सड़क पर संघर्ष के लिए वह एक मुद्दा लेकर निकला है। विपक्ष ने इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के खिलाफ सत्ता पक्ष के विरुद्ध सदन में और बाहर भी प्रदर्शन किया।

आरंभिक गतिरोध के बाद वंदे मातरम् व चुनाव सुधारों पर चर्चा से संसद पटरी पर आई। वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष चर्चा और चुनाव सुधारों के बहाने एसआइआर पर चर्चा में जो तथ्य दोनों पक्षों द्वारा सामने लाए गए, उनसे किसे राजनीतिक लाभ हुआ और किसे हानि, यह तो भविष्य में तय होगा। मगर चर्चा में सभी दलों की भागीदारी ने सकारात्मक संदेश जरूर दिया। शून्यकाल व प्रश्नकाल में जनहित से जुड़े मुद्दे भी दोनों सदनों में उठे और संबंधित मंत्रियों की ओर से जवाब दिए गए।

आठ विधेयकों को मिली संसद की मंजूरी: सूत्रों के अनुसार, सरकार की तैयारी इस सत्र में 14-15 विधेयक पारित कराने की थी। इतने तो नहीं हो सके, पर वीबी-जी राम जी विधेयक, मणिपुर जीएसटी (दूसरा संशोधन) विधेयक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक, विनियोग (संख्या चार) विधेयक, निरसन एवं संशोधन विधेयक, सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून में संशोधन) विधेयक व भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग एवं संवर्धन विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गए। प्रतिभूति बाजार कोड बिल लोस से संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया। इनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सबसे अधिक तकरार वीबी-जी राम जी बिल को लेकर हुई।

राधाकृष्णन ने विपक्ष को दी आत्मचिंतन की सलाह

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के लिए राज्यसभा के सभापति के रूप में यह पहला सत्र था। सत्र के समापन पर उन्होंने कहा, यह सत्र मेरे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पद संभालने के बाद मैंने पहली बार राज्यसभा का सभापतित्व किया। पूरे सत्र की उपलब्धियों का ब्योरा और दोनों पक्षों को सहयोग के लिए आभार व्यक्त करने के साथ ही उन्होंने कहा,कल की बैठक के दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा नारेबाजी करना, तख्तियां प्रदर्शित करना, मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर देने को बाधित करना, पत्र फाड़ना और उन्हें पीठ के समक्ष फेंकना, यह आचरण संसद सदस्यों की गरिमा के प्रतिकूल था। मैं आशा करता हूं कि सदस्य आत्मचिंतन करेंगे और भविष्य में ऐसी अव्यवस्थित व अनुचित आचरण की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। इसी तरह लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने वहां की उत्पादकता के संबंध में सदस्यों को जानकारी देते हुए सभी दलों के सहयोग की सराहना की।

Dainik Jagaran Page No-1

क्रांति, काव्य व चरित्र का अमर प्रतीक

श्रद्धांजलि
पंडित रामप्रसाद
बिस्मिल

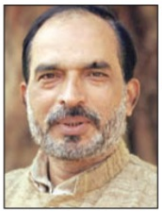

बृजेश राम त्रिपाठी

संस्थापक संयोजक
पंडित रामप्रसाद
बिस्मिल बलिदानी
मेला एवं खेल
महोत्सव

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल राजनीतिक आंदोलनों की शृंखला नही है, बल्कि वह त्याग, तपस्या, साहस और राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत ऐसे व्यक्तित्वों की गाथा है, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का स्वप्न देखा। ऐसे ही महान क्रांतिकारियों में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। वे न केवल एक निर्भीक क्रांतिकारी थे, बल्कि संवेदनशील कवि, ओजस्वी लेखक और उच्च कोटि के देशभक्त चिंतक भी थे। उनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

प्रारंभिक जीवन और संस्कार : पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ। उनके पिता मुरलीधर और माता मूलमती धार्मिक एवं संस्कारवान प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही बिस्मिल में स्वाभिमान, साहस और अन्याय के प्रति विद्रोह की भावना स्पष्ट दिखाई देती थी। आरंभिक शिक्षा के दौरान ही उन्होंने हिंदी, उर्दू और संस्कृत का अध्ययन किया तथा साहित्य के प्रति विशेष रुचि विकसित की।

किशोरावस्था में ही आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित होकर उनके मन में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीयों के शोषण ने उनके मन में यह दृढ़ विश्वास पैदा किया कि स्वतंत्रता केवल याचना से नही, बल्कि बलिदान से प्राप्त होगी।

क्रांतिकारी विचारधारा और संगठनात्मक भूमिका : रामप्रसाद बिस्मिल उन क्रांतिकारियों में थे, जिन्होंने संगठित सशस्त्र क्रांति को स्वतंत्रता का प्रभावी मार्ग माना। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के संस्थापक सदस्यों में प्रमुख थे। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंककर भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना था।1925 में जारी संगठन का घोषणापत्र, जिसे बिस्मिल ने ही लिखा, उनकी वैचारिक स्पष्टता और राजनीतिक दूरदृष्टि को दर्शाता है। इस दस्तावेज़ में आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की स्पष्ट झलक मिलती है। यह केवल सत्ता परिवर्तन का नही, बल्कि समाज परिवर्तन का सपना था।

काकोरी कांड : इतिहास का निर्णायक मोड़ : भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काकोरी कांड (9 अगस्त 1925) एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज है। इस योजना के प्रमुख सूत्रधार पंडित रामप्रसाद बिस्मिल थे। क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को रोककर धन प्राप्त किया, ताकि संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके।

यद्यपि यह घटना आर्थिक दृष्टि से सीमित थी, किंतु इसके राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव अत्यंत व्यापक थे। अंग्रेजी सरकार बुरी तरह हिल गई और उसने दमन का सहारा लिया। लंबे मुकदमे के बाद बिस्मिल सहित कई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई।

अदम्य साहस और बलिदान : 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। कहा जाता है कि फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय उनके मुख पर भय नही, बल्कि गर्व और शांति थी। वे हंसते हुए बोलते वंदे मातरम! भारत माता की जय! उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह बलिदान व्यर्थ नही गया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा मिली और युवाओं में क्रांतिकारी चेतना का विस्तार हुआ।

कवि और लेखक के रूप में बिस्मिल : पंडित रामप्रसाद बिस्मिल केवल क्रांति के प्रतीक नही थे, वे एक उत्कृष्ट कवि भी थे। उन्होंने बिस्मिल के साथ-साथ राम और अज्ञात उपनामों से काव्य रचना की। उनकी कविताओं में देशप्रेम, त्याग, वेदना और क्रांति का स्वर मुखर रूप से उपस्थित है।

उनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ -

सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है ज़ोर कितना बाज़ू-ए-क़ातिल में है।

आज भी जन-जन की जुबान पर है। यह कविता केवल शब्दों का संयोजन नही, बल्कि गुलामी के विरुद्ध चुनौती का उद्घोष है। उन्होंने आत्मकथा भी लिखी, जिसमें उनके जीवन संघर्ष, वैचारिक विकास और क्रांतिकारी अनुभवों का सजीव वर्णन मिलता है। उनका साहित्य आज भी प्रेरणादायक और प्रासंगिक है।

व्यक्तित्व के आयाम : रामप्रसाद बिस्मिल का व्यक्तित्व बहुआयामी था। एक ओर वे कठोर अनुशासन और साहस के प्रतीक थे, तो दूसरी ओर कोमल हृदय, संवेदनशील और आत्मविश्लेषण करने वाले व्यक्ति। वे धार्मिक आडंबर के विरोधी थे, किंतु नैतिकता और आदर्शों में उनकी गहरी आस्था थी। साथियों के प्रति उनकी निष्ठा, संगठन के प्रति समर्पण और व्यक्तिगत जीवन में सादगी उन्हें विशिष्ट बनाती है। वे मानते थे कि क्रांतिकारी का जीवन स्वयं के लिए नही, बल्कि राष्ट्र के लिए होता है।

आज के संदर्भ में प्रासंगिकता : आज जब देश स्वतंत्र है, तब भी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। उनका संघर्ष हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नही, बल्कि जिम्मेदारी भी है। भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के विरुद्ध संघर्ष आज भी उतना ही आवश्यक है, जितना तब था। युवाओं के लिए बिस्मिल का जीवन संदेश है कि आदर्शों के लिए संघर्ष करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। राष्ट्रप्रेम केवल नारों में नही, बल्कि कर्म में प्रकट होना चाहिए।

निष्कर्ष : पंडित रामप्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे नायक थे, जिन्होंने अपने विचारों, कृत्यों और बलिदान से इतिहास को दिशा दी। वे क्रांति के कवि थे, कविता के क्रांतिकारी थे और चरित्र के शिखर पुरुष थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जब विचार शुद्ध हों, लक्ष्य स्पष्ट हो और संकल्प अडिग हो, तब कोई भी शक्ति राष्ट्र की आत्मा को दबा नहीं सकती।आज आवश्यकता है कि हम बिस्मिल को केवल स्मरण न करें, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

Useful For Mains

आबादी के बदलते आयाम और चुनौतियां

भारत इस समय दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। मगर सामाजिक स्थितियां इशारा कर रही हैं कि इस खुशी की आयु बहुत लंबी नहीं है। देश वृद्ध आबादी के झुकते संतुलन की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।

अखिलेश श्रीवास्तव चमन

किसी भी देश या समाज की असली ताकत उसके युवा होते हैं। भारत इस समय दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार भारत की पचास फीसद से अधिक आबादी पच्चीस साल से कम उम्र के युवाओं की है और पैंतीस साल से कम उम्र के युवा भारत में पैंसठ फीसद हैं। देश के लिए यह प्रसन्नता की बात है। मगर सामाजिक स्थितियां इशारा कर रही हैं कि इस खुशी की आयु बहुत लंबी नहीं है। देश वृद्ध आबादी के झुकते संतुलन की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस बात की पुष्टि विविध आंकड़ों से भी होती है। अनुमान है कि वर्ष 2046-47 तक भारत बुजुर्गों का देश हो जाएगा। यानी यहां युवाओं की तुलना में वृद्धों की संख्या अधिक हो जाएगी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 में भारत में साठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों की आबादी 10.16 करोड़, यानी देश की कुल आबादी की लगभग 8.4 फीसद थी। अनुमान के मुताबकि, अगले दस वर्षों में यह आबादी बढ़ कर दोगुनी और कुल आबादी की 10.5 फीसद हो गई। बताया जाता है कि वर्तमान में देश में साठ वर्ष से अधिक आयु वालों की जनसंख्या कुल आबादी की लगभग बारह फीसद से कुछ अधिक है। वर्ष 2036 में देश की कुल आबादी 153 करोड़ हो सकती है और तब तक बुजुर्गों की आबादी लगभग 23 करोड़ यानी पंद्रह फीसद हो जाएगी। यानी वर्ष 2036 में देश का हर सातवां व्यक्ति साठ साल से अधिक आयु का होगा। इसी प्रकार, अनुमान है कि वर्ष 2050 में देश की लगभग 21 फीसद आबादी वरिष्ठ नागरिकों की होगी। वर्ष 2075 में भारत की कुल आबादी 1.6 अरब होने का अनुमान है, जिसमें लगभग 32 फीसद हिस्सेदारी साठ साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों की होगी। यानी 2075 में देश का हर तीसरा व्यक्ति वरिष्ठ होगा।

वर्तमान में भारत की आबादी की औसत आयु उनतीस वर्ष बताई जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में देश में पंद्रह से उनतीस वर्ष आयु के मध्य के युवाओं की कुल संख्या 37.14 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या की लगभग 28 फीसद है। इसके अलावा, पैंतीस साल से कम उम्र के युवाओं की भागीदारी 65 फीसद से भी अधिक थी, लेकिन अब इसमें गिरावट आने लगी है। अनुमान है कि वर्ष 2036 में देश की आबादी में युवाओं की भागीदारी घट कर लगभग 22.7 फीसद रह जाएगी। इस तस्वीर का साफ संकेत है कि युवा आबादी घटने से देश के जन-बल और कार्यबल में कमी आएगी।

दरअसल, पिछले दो दशकों से देश में बच्चों की आबादी भी तेजी से घट रही है। जबकि दूसरी तरफ चिकित्सा सुविधा तथा जीवन स्तर में सुधार के कारण आम आदमी की जीवन प्रत्याशा (औसत आयु) लगातार बढ़ रही है। आम आदमी की औसत आयु में वृद्धि तक तो बात ठीक है, लेकिन नवजातों की जन्म दर में कमी चिंता का विषय है। यह प्रवृत्ति इस कारण भी चिंता का विषय है कि बच्चों की जन्म दर में गिरावट आकस्मिक नहीं, बल्कि ऐच्छिक और सुविचारित भी है। इस

समस्या का एक बड़ा कारण है शादियों में विलंब तथा युवा पीढ़ी का अपने दायित्वों से पलायन। अब से लगभग चार दशक पहले शादियां औसतन पच्चीस-छब्बीस वर्ष की आयु तक हो जाया करती थीं। मगर करिअर का दबाव, जीवनशैली में बदलाव तथा सुरक्षित भविष्य की अनिश्चितता के कारण आज तीस-बत्तीस की उम्र शादी की सामान्य उम्र बन चुकी है। अधिकांश मामलों में तो यह उम्र पैंतीस या उससे भी ऊपर पहुंच चुकी है। वैवाहिक विज्ञापनों में नब्बे फीसद से अधिक युवा तीस वर्ष से अधिक आयु के होते हैं।

> **भारत की जनसंख्या नीति का उद्देश्य वर्ष 2045 तक देश की जनसंख्या दर को स्थिर करना है। हालांकि अपने देश में परिवार नियोजन को लेकर सख्ती नहीं है। फिर भी विविध माध्यमों से इसे प्रोत्साहन अवश्य दिया जा रहा है। पड़ोसी देश चीन इस तरह की सख्ती का दुष्परिणाम भुगत चुका है। चीन में वर्ष 1979 से 2015 तक एक बच्चा नीति बहुत सख्ती के साथ लागू की गई। इसका नतीजा यह निकला कि चीन में न सिर्फ वृद्धों की संख्या बढ़ गई, बल्कि समाज में स्त्री-पुरुष का अनुपात भी गड़बड़ा गया। हार कर चीन सरकार ने परिवार नियोजन संबंधी प्रतिबंध हटा लिए।**

चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, महिलाओं की प्रजनन क्षमता बीस से सत्ताईस वर्ष की आयु के दौरान चरम पर होती है। तीस वर्ष की उम्र के बाद प्राकृतिक रूप से आने वाले बदलाव की वजह से इसमें कमी आने लगती है। इसी प्रकार, पुरुषों में भी उम्र के मुताबिक कई तरह के कुदरती बदलाव आते हैं। यही कारण है कि समाज में निस्संतान दंपतियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे अंततः युवा आबादी कम हो रही है। एक और विसंगति यह है कि आज की युवा पीढ़ी विवाह को लेकर अरुचि दिखाने लगी है। कुछ युवा इस मामले में भय और विरक्ति का शिकार भी हो रहे हैं। सहजीवन के चलन से इस प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ावा मिल रहा है। न सिर्फ इतना, बल्कि विवाहित जोड़ों में भी एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो विवाह के बावजूद बच्चे पैदा करने तथा उसका पालन-पोषण करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। विशेष रूप से जहां पति और पत्नी दोनों नौकरी में हैं, वहां बच्चा पैदा करना एक अवांछित बोझ माना जाने लगा है। हालांकि इसमें घरेलू कार्य का बंटवारा एक बड़ा कारक है। संयुक्त परिवारों के विघटन ने इस सोच को और अधिक बल दिया है।

एक विरोधाभास यह है कि जहां देश में औसत मृत्यु दर में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं की मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। अध्ययन बताते हैं कि आत्महत्या तथा दुर्घटना युवाओं की मृत्यु के प्रमुख कारण बन रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार युवाओं की मौत की बड़ी वजह (17.3 फीसद से भी अधिक) आत्महत्या है। पारिवारिक जिम्मेदारी, मानसिक तनाव, असुरक्षित भविष्य, नशे की लत तथा नौकरी और पढ़ाई का दबाव आदि वे कारण हैं जो युवाओं को संकट की तरफ धकेल रहे हैं।

युवाओं की आबादी के इस रुख के पीछे एक बड़ा कारण सरकार की परिवार नियोजन की नीति भी है। पंद्रह फरवरी 2000 को घोषित भारत की जनसंख्या नीति का उद्देश्य वर्ष 2045 तक देश की जनसंख्या दर को स्थिर करना है। हालांकि अपने देश में परिवार नियोजन को लेकर सख्ती नहीं है। फिर भी विविध माध्यमों से इसे प्रोत्साहन अवश्य दिया जा रहा है। पड़ोसी देश चीन इस तरह की सख्ती का दुष्परिणाम भुगत चुका है। चीन में वर्ष 1979 से 2015 तक एक बच्चा नीति बहुत सख्ती के साथ लागू की गई। इस का नतीजा यह निकला कि चीन में न सिर्फ वृद्धों की संख्या बढ़ गई, बल्कि समाज में स्त्री-पुरुष का अनुपात भी गड़बड़ा गया। कारण कि एक ही बच्चा पैदा करने की अनिवार्यता की स्थिति में अधिकांश दंपति बेटे को वरीयता देने लगे थे। हार कर चीन सरकार ने 2016 में दो बच्चे पैदा करने की छूट दी। उससे भी बात बनती नहीं दिखी तो मई 2021 में तीन बच्चों तक की अनुमति दी गई। अंततः 26 जुलाई 2021 से चीन सरकार ने परिवार नियोजन संबंधी सारे प्रतिबंध हटा लिए। अब चीनी दंपति जितना चाहें, उतने बच्चे पैदा कर सकते हैं।

हमें चीन की इस असहज स्थिति से सबक लेना चाहिए। देश की घटती युवा शक्ति भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। लिहाजा अपने देश में युवाओं की घटती संख्या को अब गंभीरता से लिया जाए और भविष्य में भारत को बुजुर्गों का देश होने से बचा लिया जाए।

Jansatta Page No-6

वैश्विक खाद्य प्रणाली बन रही तापमान वृद्धि का कारण

पिछले 40 सालों में मोटापे के कारणों में खाने की चीजों की खपत में आया बदलाव भी है शामिल

विशेषज्ञों ने स्वस्थ खाद्य पदार्थों के लिए सब्सिडी व अस्वास्थ्यकर पदार्थों के लिए कर लगाने का दिया सुझाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : वर्तमान वैश्विक खाद्य प्रणाली पेरिस समझौते में निर्धारित दो डिग्री सेल्सियस के तापमान सीमा को पार कर सकती है, भले ही आज से जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन समाप्त हो जाएं। एक अध्ययन के अनुसार यह जानकारी सामने आई है।

यूके, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और सिंगापुर के अंतरराष्ट्रीय शोध दल ने कहा कि वैश्विक खाद्य प्रणाली मोटापे के अलावा दोहरे संकट को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन के अलावा ज्यादा कैलोरी वाले, कम फाइबर वाले प्रोडक्ट्स, जिनमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं। हाल में 'फ्रंटियर्स इन साईंस' पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में यह उजागर किया गया है कि अस्थायी, लाभ प्रेरित खाद्य प्रणालियों से निपटना स्वास्थ्य और जलवायु दोनों के लिए कितना आवश्यक है।

जलवायु संकट से निपटने के लिए उत्सर्जन को बढ़ाने वाली खाद्य प्रणालियों को निपटना होगा

प्रतीकात्मक

मोटापा कर रहा सभी को प्रभावित : लेखकों ने कहा कि मोटापा तेजी से युवा और निम्न आय जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने इलाज के लंबे समय तक किफायती होने, सुरक्षा और दुनिया भर में लगातार उपलब्धता को लेकर भी चिंता जताई। यूके की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के मुख्य शोधकर्ता जेफ हाली ने कहा, हालांकि मोटापा एक जटिल बीमारी है जो कई आपस में जुड़े कारणों से होती है, लेकिन इसका मुख्य कारण पिछले 40 सालों में खाने की चीजों के सिस्टम में खपत की वजह से आया बदलाव है।

खाद्य प्रणाली को बदलना ज्यादा लाभदायक : होली ने कहा, वजन कम करने वाली दवाओं या सर्जरी के उलट इस वजह पर ध्यान देने से इंसानों और पृथ्वी को फायदा होगा। शोध लेखकों ने स्वस्थ खाद्य पदार्थों के लिए सब्सिडी, खास तौर पर अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के लिए कर और चेतावनी लगाने व ज्यादा कैलोरी, कम फाइबर वाले प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पर रोक लगाने की सलाह दी है, विशेष रूप से निम्न-आय समुदायों व बच्चों के लिए।

कई बीमारियों का कारण है मोटापा

टीम ने कहा कि 2035 तक दुनिया की आधी आबादी का वजन ज्यादा या मोटापे का शिकार होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि वैश्विक तापमान वृद्धि अब दुनिया भर में हर मिनट एक व्यक्ति की जान ले रही है, जिससे 2012-2021 की अवधि में सालाना लगभग 5,46,000 मौतें हुईं, जो 1990 के दशक की तुलना में 63 प्रतिशत ज्यादा है। खाद्य उत्पादन को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के एक चौथाई से एक तिहाई के लिए जिम्मेदार पाया गया और यह भूमि की सफाई का मुख्य कारण है।

उत्सर्जन को बढ़ाने वाली खाद्य प्रणालियों को निपटना होगा

यूके की आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पहले लेखक पाल बेहरेस ने कहा, बिना यह बदले कि हम क्या खाते हैं और इसे कैसे उत्पादन करते हैं, हम जलवायु संकट को हल नहीं कर सकते। जलवायु संकट से निपटने के लिए हमें उन खाद्य प्रणालियों से निपटना होगा जो उत्सर्जन को बढ़ाती हैं और हमें ऊर्जा घनत्व और अत्यधिक प्रसंस्कृत आहारों की ओर धकेलती हैं, जिनमें पशु उत्पाद शामिल हैं। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि आहार को न्यूनतम प्रसंस्कृत, फाइबर समृद्ध पौधों के खाद्य पदार्थों को स्थानांतरित किया जाए। स्वस्थ खाद्य से वजन बढ़ने को रोकना कम हानिकारक और बहुत सस्ता होगा, बजाय इसके कि मोटापे व जलवायु परिवर्तन के परिणामों के अनुकूलन के लिए।

Dainik Jagaran Page No-14

लोक नीति विश्लेषक

भारत की वैश्विक रणनीति का विस्तार

पीएम मोदी की जार्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा केवल एक औपचारिक राजनयिक यात्रा ही नहीं थी, बल्कि यह भारत की बदलती वैश्विक रणनीति, भूमिका और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर आधारित विदेश नीति का स्पष्ट संकेत भी थी। ये तीनों देश भौगोलिक दृष्टि से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों पश्चिम एशिया, अफ्रीका और अरब सागर क्षेत्र में स्थित हैं, किंतु भारत के साथ इनके संबंध अत्यंत गहराई से जुड़े हुए हैं

अदीस अबाबा में कुशवार को संसद के संयुक्त सत्र के संबोधन के लिए पहुंचने पर पीएम मोदी का अभिवादन करते इथियोपियाई सांसद। प्रेट

हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीन देशों की यात्रा संपन्न हुई। जार्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा केवल एक औपचारिक राजनयिक यात्रा ही नहीं थी, बल्कि यह भारत की बदलती वैश्विक रणनीति, भूमिका और बहुपक्षीय तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर आधारित विदेश नीति का स्पष्ट संकेत भी थी। ये तीनों देश भौगोलिक दृष्टि से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों पश्चिम एशिया, अफ्रीका और अरब सागर क्षेत्र में स्थित हैं, किंतु भारत के साथ इनके संबंध प्राचीन सभ्यतागत, ऐतिहासिक और समकालीन रणनीतिक स्तर पर अत्यंत गहराई से जुड़े हुए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की जार्डन यात्रा ऐसे समय हुई है, जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। जार्डन पश्चिम एशिया में एक स्थिर, उदार और संतुलित भूमिका में रहने वाला देश है तथा क्षेत्रीय शांति प्रयासों में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जार्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय के साथ वार्ता में राजनीतिक सहयोग, रक्षा संवाद, आतंकवाद-रोधी सहयोग, जल संसाधन प्रबंधन और शिक्षा जैसे विषय रहे। विशेष रूप से रक्षा सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच नियमित संवाद और संयुक्त प्रशिक्षण ने द्विपक्षीय विश्वास को मजबूत किया है। भारत और जार्डन के बीच वैसे पहले से ही संबंध पारंपरिक रूप से सौहार्दपूर्ण रहे हैं, किंतु पिछले एक दशक में नियमित उच्च स्तरीय संवाद, रक्षा सहयोग समझौते और व्यापारिक संवाद ने दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई और विश्वास प्रदान किया है।

यात्रा के अगले पड़ाव के रूप में इथियोपिया की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली यात्रा थी और यह अफ्रीका के साथ भारत की गहरी साझेदारी को रेखांकित करती है। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा आज वैश्विक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है, जो अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है। भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को जी20 का स्थायी सदस्य बनाना इसी दृष्टिकोण का परिणाम था कि ग्लोबल साउथ की आवाज को वैश्विक मंच पर समुचित प्रतिनिधित्व मिले। भारत की इस दिशा में भूमिका भी उल्लेखनीय रही थी। प्रधानमंत्री की इथियोपिया के प्रधानमंत्री डा. अबी अहमद अली के साथ हुई बातचीत में विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और रक्षा सहयोग जैसे विषय शामिल रहे। भारत पहले से ही इथियोपिया में शिक्षा, आइटी और स्वास्थ्य क्षेत्र में एक भरोसेमंद साझेदार रहा है। मोदी सरकार से पहले भारत-अफ्रीका संबंध मुख्यतः सहायता और व्यापार तक सीमित थे। किंतु पिछले दस वर्षों में इन्हें साझेदारी और सह-विकास के माडल में बदला गया है। इथियोपिया की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में प्रस्तुत करना और विकास की भारतीय यात्रा साझा करना इस नए आत्मविश्वास का प्रतीक है।

अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ओमान गए। यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब भारत और ओमान अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ओमान ऐतिहासिक रूप से भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री और व्यापारिक साझेदार रहा है। अरब सागर क्षेत्र में इसकी रणनीतिक स्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद के बीच हुई बातचीत में भी रणनीतिक साझेदारी, ऊर्जा सहयोग, निवेश, बंदरगाह विकास और रक्षा सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। ओमान भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र में एक भरोसेमंद मित्र रहा है, जिसने कठिन समय में भी भारत के हितों का सम्मान किया है। मोदी सरकार से पहले भारत-ओमान संबंध स्थिर तो थे, लेकिन उनमें रणनीतिक गहराई का अभाव था। पिछले कुछ वर्षों में रक्षा लाजिस्टिक्स सहयोग, समुद्री सुरक्षा संवाद और निवेश सहयोग ने इस रिश्ते को नई ऊंचाई दी है। तीनों देशों के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता इसका प्रमाण है।

इन तीन देशों की यात्रा से भारत को कई स्तरों पर लाभ हुआ है। पहला, राजनीतिक स्तर पर भारत की विश्वसनीयता और सक्रियता को बल मिला है। दूसरा, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई दिशा मिली है, विशेषकर आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में। तीसरा, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को विस्तार देने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। चौथा, प्रवासी भारतीयों की भूमिका को औपचारिक रूप से मान्यता और प्रोत्साहन मिला है।

वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहां एकध्रुवीय व्यवस्था कमजोर हो रही है और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था आकार ले रही है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री की जार्डन, इथियोपिया और ओमान यात्रा भारत की विदेश नीति के रणनीतिक पुनर्संतुलन का संकेत देती है। नीतिगत दृष्टि से यह यात्रा तीन अहम स्तंभों को रेखांकित करती है। पहला, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। इथियोपिया के माध्यम से भारत ने यह संदेश दिया है कि वह केवल सहायता देने वाला नहीं, बल्कि नीति-निर्माण में भागीदार देश है। जी20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता इसी की परिणति है। दूसरा, पश्चिम एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता। जार्डन और ओमान क्षेत्रीय संतुलन, आतंकवाद-रोधी सहयोग और समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओमान के साथ समुद्री और रक्षा लाजिस्टिक्स सहयोग भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति को मजबूती देता है, जबकि जार्डन के साथ संवाद पश्चिम एशिया में भारत की विश्वसनीय छवि को सुदृढ़ करता है। तीसरा, ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी सुरक्षा। ओमान और जार्डन भारत की ऊर्जा आपूर्ति शृंखला तथा वैकल्पिक व्यापार मार्गों के लिए अहम हैं। इथियोपिया अफ्रीका में निवेश और विकास साझेदारी का प्रवेश द्वार है।

ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज बनता भारत

प्रधानमंत्री मोदी की जार्डन, इथियोपिया और ओमान यात्रा भारत की विदेश नीति में आए आत्मविश्वास, स्पष्टता और दूरदर्शिता का प्रतीक है। ये यात्राएं दिखाती हैं कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, बल्कि वैश्विक घटनाक्रम को दिशा देने वाला देश बन रहा है। सभ्यतागत मूल्यों और समकालीन हितों के संतुलन के साथ आगे बढ़ती यह कूटनीति भारत को ग्लोबल साउथ की एक सशक्त आवाज और विश्व मंच पर एक जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित कर रही है। इन तीन देशों की यात्राओं से प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को एक सार्थक और सकारात्मक संदेश तो दिया ही है, साथ ही भविष्य के लिए भी कुछ संकेतों को छोड़ा है। भारत अब वैश्विक नीति को निर्धरता से साझेदारी और उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करता जा रहा है।

प्रधानमंत्री की जार्डन, इथियोपिया और ओमान यात्रा का प्रभाव केवल द्विपक्षीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक असर भारत के क्षेत्रीय और वैश्विक संबंधों पर भी पड़ता है। नई विश्व व्यवस्था के संदर्भ में देखें तो यह यात्रा भारत की विश्वसनीय, संतुलित और सक्रिय शक्ति की छवि को और मजबूत करती है। इससे पश्चिम एशिया के अन्य देशों जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और मिस्र के साथ भारत के संबंधों को यह संदेश जाता है कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता, संवाद और विकास का समर्थक है। जार्डन और ओमान जैसे संतुलित देशों के साथ मजबूत रिश्ते भारत को पश्चिम एशिया में एक नान-पोलराइजिंग पार्टनर के रूप में स्थापित करते हैं, जिससे भारत की स्वीकार्यता बढ़ती है। दूसरी तरफ अफ्रीकी देशों के साथ भारत की स्थिति और सुदृढ़ होती जा रही है। इथियोपिया और अफ्रीकी संघ के साथ बेहतर संवाद से अन्य अफ्रीकी देशों को भी सकारात्मक संकेत मिलता है कि भारत उनकी विकास प्राथमिकताओं को समझता है और समान भागीदारी के सिद्धांत पर सहयोग करता है। इससे भारत को चीन-केंद्रित विकास माडल के विकल्प के रूप में भी देखा जाने लगा है।

आज के संदर्भ में देखें तो वैश्विक शक्तियों अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान के साथ भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है। यह यात्रा दिखाती है कि भारत रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए विभिन्न भू-राजनीतिक क्षेत्रों में स्थिर संबंध साध सकता है। इससे भारत को एक ब्रिजिंग पावर के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका मजबूत हुई है, जिसका सकारात्मक असर आसियान और अफ्रीका के पूर्वी तट के देशों के साथ संबंधों पर पड़ता है। इस प्रकार यह यात्रा भारत को एक नेटवर्क्ड, भरोसेमंद और दीर्घकालिक साझेदार के रूप में स्थापित करती है, जिससे अन्य देशों के साथ उसके संबंध और गहराते हैं।

आगे की रणनीति के तहत भारत को इन देशों के साथ संबंधों को केवल द्विपक्षीय नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संदर्भ में भी देखना होगा। जार्डन के साथ पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के प्रयासों में सहयोग बढ़ाया जा सकता है। इथियोपिया के माध्यम से अफ्रीका में भारत की विकास साझेदारी को संस्थागत रूप दिया जा सकता है। ओमान के साथ समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा को दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यापार संतुलन, निवेश सुविधा, जनसंपर्क और संस्कृतिक आदान-प्रदान को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। थिंक टैंक, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

-गौरव कुमार

Dainik Jagaran Page No-9

अरावली की सुरक्षा का सवाल

रंजना मिश्रा

अरावली पर्वतमाला केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि यह उत्तर भारत के करोड़ों लोगों के लिए एक रक्षा कवच है

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत शृंखला को बचाने के लिए जो रुख अपनाया, वह हमारे पर्यावरण के भविष्य के लिए एक निर्णायक मोड़ है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक है, जो राजस्थान के रेगिस्तान को दिल्ली और हरियाणा की ओर बढ़ने से रोकती है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में अवैध खनन और अनियंत्रित शहरीकरण ने इन पहाड़ियों को छलनी कर दिया है। कोर्ट का ताजा फैसला इसी बर्बादी को रोकने की एक गंभीर कोशिश है। कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली इन पहाड़ियों पर किसी भी नए खनन पट्टे पर तब तक के लिए रोक लगा दी है, जब तक कि केंद्र सरकार इसके लिए एक वैज्ञानिक प्रबंधन योजना तैयार नहीं कर लेती। कोर्ट ने महसूस किया कि अगर अरावली खत्म हो गई तो उत्तर भारत में धूल भरी आंधियों और मरुस्थलीकरण को कोई नहीं रोक पाएगा।

अरावली की परिभाषा को लेकर कोर्ट ने कहा है कि अनुसार समुद्र तल से 100 मीटर से अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही सुरक्षा के दायरे में रखा जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, लेकिन वह जैव-विविधता और भूजल संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। यदि केवल ऊंची पहाड़ियों को बचाया गया तो नीची पहाड़ियों पर खनन का खतरा बढ़ सकता है। वैसे कोर्ट ने इस मुद्दे पर भी सरकार को संतुलन बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एक व्यावहारिक बात कही है कि पूरी तरह से खनन बंद करना भी समाधान नहीं है, क्योंकि इससे अवैध खनन माफिया और अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए कोर्ट ने सतत खनन प्रबंधन योजना की मांग की है। इसका मतलब है कि केवल वहीं खनन होगा, जहां पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और जहां से मिलने वाला राजस्व अरावली के पुनर्वास पर ही खर्च किया जाए। कोर्ट का यह नजरिया बताता है कि वह विकास और पर्यावरण के बीच एक पुल बनाना चाहता है। इस कानूनी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण पहलू इको-सेंसिटिव जोन और ग्रीन बाल का है। अरावली में अब पांच किलोमीटर के बफर जोन की बात की जा रही है, जहां कोई भी भारी निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। इसे एक हरी दीवार के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके और वन्यजीवों के लिए एक सुरक्षित गलियारा बनाया जा सके। अरावली की पहाड़ियां बारिश के पानी को जमीन के भीतर भेजने का सबसे बड़ा स्रोत हैं। यदि ये पहाड़ियां कट गईं तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली जैसे शहरों में जलस्तर तेजी से गिरेगा।

खनन पर यह रोक केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे रोकने के लिए सैटेलाइट निगरानी और स्थानीय प्रशासन की ईमानदारी बेहद जरूरी है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

Dainik Jagaran Page No-8

भारतीय धरोहर की वैश्विक स्वीकार्यता

शिशिर शुक्ला

दीपावली का यूनेस्को सूची में आना देश की सांस्कृतिक शक्ति से विश्व को परिचित कराने का एक अवसर भी है

भारतीय संस्कृति की आभा से अभिभूत विश्व। फाइल

अंधकार पर प्रकाश की विजय के पर्व दीपावली को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारत के लिए यह एक उपलब्धि है। अभी तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत की 15 धरोहरें शामिल थीं। इनमें कुंभ मेला, गुजरात का गरबा नृत्य, कोलकाता की दुर्गा पूजा, योग, वेद पाठ, रामलीला, छाऊ नृत्य, नवरोज त्योहार, कालबेलिया नृत्य प्रमुख हैं। दीपावली को 16वीं अमूर्त विरासत के रूप में यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया है। भारत की सांस्कृतिक परंपराएं महज अतीत का एक प्रमाण मात्र ही नहीं हैं, अपितु वे पूर्णतया जीवंत हैं और प्रत्येक भारतीय के जीवन के सूक्ष्म अनुभवों में धड़कती हैं।

भारत अपने त्योहारों, रीति-रिवाजों, लोककथाओं, संगीत, नृत्य, खान-पान और सामाजिक व्यवहारों के माध्यम से केवल अपना अतीत ही नहीं संभालता, बल्कि अपने आत्मा को भी जीवंत रखता है। जब कोई सांस्कृतिक परंपरा वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित होती है, तो उसके अर्थ एवं भाव स्थानीयता से उठकर सार्वभौमिकता की ओर बढ़ जाते हैं। यूनेस्को ने दीपावली को न केवल एक त्योहार के रूप में देखा, बल्कि एक सांस्कृतिक दर्शन के रूप में पहचाना, जो अनंत काल से हमारे समाज का अभिन्न अंग बना हुआ है। भारत का सांस्कृतिक तंत्र जितना विशाल है, उतना ही जटिल भी है। यहां पग-पग पर भाषा, भोजन की शैली, पहनावा, लोकगीतों का सुर, त्योहारों की परंपरा, आचार-विचार आदि भिन्न रूप ग्रहण करते हुए सामने आते हैं, किंतु इन तमाम विविधताओं को एक सूत्र में बांधने का कार्य उसी विविधता में विद्यमान एकता के द्वारा किया जाता है। दीपावली का त्योहार इस एकतासूत्र का सर्वोत्तम उदाहरण है। देश के विभिन्न हिस्सों में हर जगह दीपों की संख्या भले ही अलग हो, किंतु प्रकाश का अर्थ, स्वरूप एवं उसमें निहित संदेश एक ही रहता है। इस व्यापकता और बहुस्तरीयता को समझना अपने आप में भारत की सांस्कृतिक शक्ति को समझना है। दीपावली का यूनेस्को सूची में शामिल होना एक सांस्कृतिक उपलब्धि भर नहीं है, बल्कि भारत के लिए व्यापक अवसर है-सांस्कृतिक संवाद को विस्तार देने का, वैश्विक प्रभाव बढ़ाने का और आने वाली पीढ़ियों में सांस्कृतिक आत्मविश्वास जगाने का। हम इस अवसर का उपयोग सांस्कृतिक संवर्धन, आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक सामंजस्य के रूप में कर सकें तो बेहतर, क्योंकि भविष्य में दीपावली के अवसर पर विदेशी पर्यटक भी भारत की ओर भ्रमण हेतु उन्मुख होंगे। इससे हमारे सांस्कृतिक एवं परंपरागत उद्योग तथा कौशल विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सक्षम हो सकेंगे।

विश्व का कोई भी देश हो, वहां पर भारतीयता किसी न किसी रूप में अवश्य मौजूद है। दुनिया भर के भारतवंशी दीपावली को उसी स्तर की वैश्विक स्वीकार्यता दिला सकते हैं, जैसी क्रिसमस अथवा न्यू ईयर को मिली हुई है। विभिन्न देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को दीपावली संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने में योगदान देना चाहिए। भारतीय दूतावासों-उच्चायोगों को भी इस दिशा में पहल करनी होगी। वैश्विक स्वीकार्यता का अर्थ केवल अंतरराष्ट्रीय सम्मान अर्जित कर लेना ही नहीं है। इस स्वीकार्यता के साथ जिम्मेदारियां भी समानुपात में बढ़ती हैं। वैश्वीकरण के दौर में काफी कुछ बाजार की चमक में अपना मूल रूप खो देता है, लिहाजा दीपावली के मूल तत्वों को सुरक्षित रखना आज और भी आवश्यक एवं चुनौतीपूर्ण हो गया है। यह त्योहार मानव सभ्यता की गहरी सांस्कृतिक परतों में अध्ययन का विषय बनना चाहिए। आज पश्चिमी जगत में बहुत सी सांस्कृतिक परंपराएं महज उत्सवों की औपचारिकताओं में सिमट गई हैं। इसके विपरीत भारत में लोक संस्कृति आज भी जीवित है। यह जीवंतता ही भारत को सांस्कृतिक रूप से अनूठा बनाती है। विश्व राजनीति में संप्रभुता वह शक्ति है जो सांस्कृतिक आकर्षण और नैतिक प्रभाव के माध्यम से देशों को जोड़ती है। योग, आयुर्वेद, भारतीय भोजन, भारतीय सिनेमा, भारतीय संगीत और अब दीपावली, ये सब भारत की संप्रभुता के स्तंभ बन चुके हैं। जब कोई राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से विश्व पटल पर पहचान बनाता है, तो उसकी वैश्विक छवि अधिक सकारात्मक बनती है और उसकी अंतरराष्ट्रीय भूमिका भी अधिक प्रभावी हो जाती है। पर्यटन, सांस्कृतिक उद्योग, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, लोकनृत्य, पारंपरिक खानपान, इन सभी क्षेत्रों को वैश्विक मंच मिलता है।

आज जब सभ्यताएं संघर्षों से गुजर रही हैं, तब एक ऐसा सांस्कृतिक संदेश जो प्रकाश, उत्साह, एकता और शुभता की बात करता है, वह मानवता के लिए एक दिशासूचक बन सकता है। यूनेस्को का यह निर्णय भारत को एक नवीन जिम्मेदारी सौंपता है और वह है अपनी संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जागरण। आधुनिक पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना, त्योहारों को उनके वास्तविक अर्थ के साथ जीना और विदेशी प्रभावों एवं बाजारीकरण के बीच अपने सांस्कृतिक आत्मा को सुरक्षित रखना, ये उद्देश्य प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दीपावली की वैश्विक मान्यता हमें स्मरण कराती है कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं केवल धार्मिक या सामाजिक व्यवहार नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के अर्थ को समृद्ध करने में भी महती भूमिका का निर्वहन करती हैं।

(लेखक अस्टिटेंट प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

उच्च शिक्षा में सुधार की सार्थक पहल

प्रो. रसाल सिंह

उच्च शिक्षा के लिए नया एकीकृत आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों के दोहरे - तिहरे नियमन की वर्तमान व्यवस्था को सुगम बनाएगा

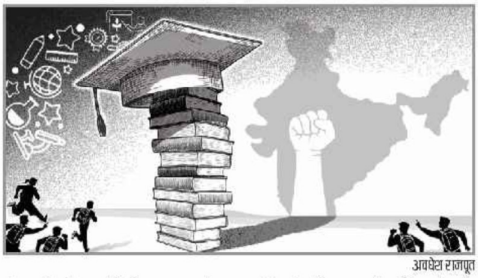

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समाप्ति) विधेयक, 2018 में आंशिक परिवर्तन करते हुए उसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' नाम से पारित नया विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को विचारार्थ प्रेषित किया गया है। यह समूचे उच्च शिक्षा क्षेत्र का एकमात्र नियामक तंत्र होगा। हालांकि, चिकित्सा शिक्षा, फार्मेसी और विधि की शिक्षा इसके दायरे में नहीं होगी। अभी उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनेक नियामक संस्थाएं कार्यरत हैं। उनके अपने-अपने मानदंड हैं। यूजीसी, एआइसीटीई, एनसीटीई, वास्तु परिषद, कृषि विज्ञान अनुसंधान परिषद, दूरस्थ और मुक्त शिक्षा, आनलाइन और डिजिटल शिक्षा तंत्र, आइसीएसएसआर, आइसीएआर, नैक, एनआइआरएफ जैसी एक दर्जन से अधिक नियामक संस्थाएं देश के कला, विज्ञान, व्यवसाय, अभियांत्रिकी, शिक्षा, प्रबंधन, कृषि शिक्षा आदि अनुशासनों से संबंधित उच्च शिक्षण संस्थाओं एवं शोध-संस्थानों की संबद्धता, मूल्यांकन, प्रत्यायन, रैंकिंग, वित्तपोषण और नियंत्रण आदि काम करती हैं। इन अलग-अलग नियामक संस्थाओं के अधीन उच्च शिक्षा पृथक्करण और बहुपरतीय नियंत्रण का शिकार थी।

देश भर में ऐसे अनेक उच्च शिक्षण एवं शोध-संस्थान हैं, जहां एक साथ कई प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं और उनसे संबंधित शोध-कार्य किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी संस्थानों को क्रमशः बहु-अनुशासनिक बनाने पर जोर दिया गया है। विभिन्न पेशेवर और परंपरागत संस्थानों की आपसी दूरी और अलगाव के 'स्टील फ्रेम' की क्रमिक समाप्ति की जा रही है। नया आयोग भारत में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और सर्वसुलभ बनाने के लिए उत्तरदायी होगा। इन बहु-अनुशासनिक उच्च शिक्षण संस्थानों एवं शोध-संस्थानों को अलग-अलग नियामक संस्थाओं का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। इस प्रक्रिया में ये संस्थान अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते रहे हैं। कई बार इन नियामक संस्थाओं में अनियमितता एवं पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का दोषारोपण भी होता रहा है। पाठ्यक्रमों के निर्माण एवं उनके कार्यान्वयन में भी ये नियामक संस्थाएं दोषमुक्त नहीं रही हैं। ये स्वायत्त नियामक संस्थाएं आपसी टकराव और अंतर्विरोध का भी शिकार रही हैं। इससे संबंधित संस्थानों को अनावश्यक अड़चन और अवरोध का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार ने इन सभी नियामक संस्थाओं की कार्यशैली का मूल्यांकन करते हुए इन्हें एक सर्वसक्षम निकाय के अधीन लाने का निर्णय लिया है।

अवधेश राजपूत

नई व्यवस्था में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान सीधे शिक्षा मंत्रालय की निगरानी में काम करेगा। यह यूजीसी एक्ट-1956, एआइसीटीई एक्ट-1987 और एनसीटीई एक्ट-1993 का स्थान लेगा। ऐसे एकल और केंद्रीकृत निकाय की संस्तुति राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2009) और यशपाल समिति (2010) ने भी की थी। यह आयोग विभिन्न संस्थाओं के आपसी सामंजस्य, समन्वय और सक्रियता के अभाव और लालफीताशाही के प्रभाव की समाप्ति और जवाबदेही और पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। चेयरमैन के अलावा इसके 12 सदस्य और होंगे। इस आयोग के विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद, विकसित भारत मानक परिषद और विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद जैसे तीन आयाम (वर्टिकल) होंगे। ये आयाम नियमन, मान्यता और व्यावसायिक मानक निर्धारण का कार्य करेंगे। निर्धारित मानकों, प्रक्रियाओं और गुणवत्ता का अनुपालन न करने वाले संस्थानों पर 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपये तक जुर्माने का भी नई व्यवस्था में प्रविधान हुआ है। यह आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों के दोहरे-तिहरे नियमन की मौजूद व्यवस्था का सरलीकरण करेगा, ताकि शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन में दोहरा/तिहरा हस्तक्षेप न हो। इस आयोग द्वारा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के संबंध में पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण और योग्यता आधारित निर्णय के माध्यम से विनियमन किया जाएगा।

इस आयोग को लर्निंग आउटकम पर विशेष ध्यान देने के अलावा शैक्षणिक मानकों में सुधार, संस्थानों के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन, संस्थानों का परामर्श, शिक्षकों का प्रशिक्षण, अधुनातन शैक्षिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने आदि का काम भी करना होगा। यह आयोग संस्थानों के नियमन और संचालन के लिए अनुकूलित वातावरण बनाते हुए अधिक लचीलेपन के साथ स्वायत्तता प्रदान करेगा। इस आयोग के पास उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने तथा स्तरहीन और कागजी संस्थानों को बंद कराने की शक्ति भी होगी। इस एकीकृत और सर्वसक्षम आयोग के गठन से समय, श्रम-ऊर्जा, संसाधन और धन की भी बचत होगी। यह नई पहल बहुत सार्थक है, लेकिन यह भी समझना होगा कि शिक्षा तंत्र को सिर्फ सरकार का दायित्व न मानकर सभी हितधारकों को उसमें भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। नियुक्ति प्रक्रिया में गुणवत्ता और पारदर्शिता, संचालन में दूरदर्शिता और सक्षमता, आधारभूत ढांचे के निर्माण में आंशिक और आनुपातिक भागीदारी और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सभी हितधारकों को अपना सर्वोत्तम योगदान देने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। दायित्व-विमुख और अधिकार-सचेत बौद्धिक समाज उच्च शिक्षा तंत्र न तो सरकार से प्रश्न पूछने का नैतिक साहस रखता है और न ही देश और समाज का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है। यह हास्यास्पद ही है कि कुछ विपक्षी और दक्षिण भारत के सांसदों ने इस अधिष्ठान के नाम पर तंज कसते हुए इसे हिंदी थोपने की कोशिश बताया है। ध्यान रहे कि यह सकारात्मक सुधारों को स्वीकारते हुए उनके बेहतर कार्यान्वयन की दिशा में संगठित प्रयास करने का समय है। अन्यथा उच्च शिक्षा तंत्र भी स्कूली शिक्षा तंत्र की गति को प्राप्त हो जाएगा।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कालेज में प्राचार्य हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

न तो गांधी पर हमला और न ही राम की अनदेखी

सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर 'विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण' (VB-GRAM G) करने का प्रस्ताव पेश किया है. इसको लेकर जबरदस्त बवाल चल रहा है। संसद में गुरुवार को इस पर चर्चा होगी. मगर सवाल तो ये है कि इसमें न तो गांधी पर हमला हुआ है और न ही राम की अनदेखी की गई है। फिर भी इस पर इतना हंगामा क्यों बरपा है? न तो गांधी पर हमला और न ही राम की अनदेखी... फिर इस बिल को लेकर इतना हंगामा क्यों?

शेक्सपियर के मशहूर नाटक रोमियो एंड जूलियट की एक लाइन है- Whats in a Name! यानी नाम में क्या रखा है। आज अगर शेक्सपियर होते तो भारत की संसद उन्हें बताती कि श्रीमान शेक्सपियर महोदय, नाम में बहुत कुछ रखा है. संसद अब सिर्फ नाम पर ही बहस करेगी क्योंकि मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार द्वारा लाई गई योजना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने मंगलवार को इसके नये प्रारूप और नामकरण का बिल लोकसभा में पेश कर दिया। इसे लेकर खूब हंगामा मचा है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी हर योजना को खारिज कर रही है. प्रियंका गांधी इसे ले कर काफी मुखर है। पर कृषि मंत्री का कहना है कि नयी योजना पूरी तरह बदल दी गई है, इसलिए यह नई योजना है।

VB-G RAM G केंद्र सरकार ने तय किया है कि विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G) अब मनरेगा का नया नाम होगा। इसमें 125 दिनों के काम की गारंटी है जबकि मनरेगा में 100 दिन थे। इसके अतिरिक्त इसमें राज्यों द्वारा देय राशि बढ़ा कर 40 कर दी गई है। पहले यह 25 या उससे कम थी। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना 2005 में मनमोहन सरकार ने पास की थी। अब इसका नाम बदलने के लिए पहले केंद्र सरकार ने पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखने की सोची किंतु अधिसूचना जारी होने के पहले ही यह नया नाम लीक हो गया और प्रियंका गांधी ने इसे महात्मा गांधी की अस्मिता से जोड़ कर हंगामा किया। तत्काल केंद्र सरकार ने यह नाम दे कर महात्मा गांधी के समक्ष राम जी को खड़ा कर दिया। अब इस योजना के विरोध का अर्थ है राम जी का अपमान। इसलिए इसे लेकर अब सरकार मोर्चा बांध रही है।

शंभूनाथ शुक्ल
वरिष्ठ पत्रकार

राम का नाम बदनाम न करो कृषि मंत्री द्वारा इसे लोकसभा में पेश करते ही हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने मनरेगा के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने का विरोध शुरू कर दिया लेकिन वही हुआ जैसा भाजपा ने सोचा था। उसने फौरन हमला किया कि कांग्रेस राम के नाम से चिढ़ती है इसलिए उसके सांसद राम के नाम से भड़क गए है। इस बात को लेकर भी प्रियंका गांधी ने तीखा विरोध किया कि ग्रामीण रोजगार योजना में अब राज्यों पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। उन्होंने इस बिल को वापस लेने का अनुरोध किया और एक बड़ी मार्मिक बात कही कि महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं थे लेकिन महात्मा गांधी पूरे देश के है इसलिए उनका नाम मनरेगा कार्यक्रम से न हटाया जाए. कांग्रेस के लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने हंसी-हंसी में कहा, राम का नाम बदनाम न करो। शशि थरूर आजकल फिर से कांग्रेस की तरफ अग्रसर है। सरकार से दूर खिसक रहे है।

फिर इस बिल को लेकर इतना हंगामा क्यों?

महात्मा गांधी और राम का नाम! समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने कहा कि राम को हे राम न करो। करीब-करीब संपूर्ण विपक्ष ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाये जाने का विरोध किया। कृषि मंत्री शिवराज चौहान यही सफाई देते रहे कि हमने इसका बजट बढ़ाया है और रोजगार के दिन भी बढ़ाए है। लेकिन असल झगड़ा शुरू हुआ महात्मा गांधी के राम राज्य की कल्पना और भाजपा के राम के नाम पर। अलबत्ता संसद में यह पहली बार हुआ कि न तो कोई राम के नाम पर विरोध कर सका न महात्मा गांधी के नाम को ले कर। गांधी बनाम राम यह भी दिलचस्प है कि महात्मा गांधी ने भी राम के नाम का ही सहारा लिया था और एक स्वस्थ लोकतंत्र तथा न्यायी राज की स्थापना के लिए उन्होंने भी राम राज्य की कल्पना की थी। सर्व धर्म समभाव के लिए ही उन्होंने रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम! की ही प्रार्थना सदैव की। इन लाइनों के बाद यह भी जुड़वाया- ईश्वर, अल्ला तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान! इन लाइनों में हिंदू-मुस्लिम एकता की भावना का आह्वान किया गया है. यानी ईश्वर और अल्ला सब एक-दूसरे के पर्याय है। ऐसे राम और ऐसे महात्मा गांधी को लेकर संसद में हमले हो रहे हैं. यह सब को पता है कि न तो गांधी पर हमला हो सकता है न राम की अनदेखी की जा सकती है। लेकिन मनरेगा के नाम को बदले जाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस इन्हीं नामों का सहारा ले कर भिड़े हैं।

बजट भी बढ़ा यह सच है कि इस योजना का नाम भी बदला गया है और बजट भी बढ़ाया गया है। इसका बजट अब 151282 करोड़ कर दिया गया है। योजना अब 125 दिनों के रोजगार को पुख़्ता करेगी लेकिन इस खर्च का बोझ राज्यों पर पड़ेगा। केंद्र सरकार 95692 करोड़ देगी और शेष 55590 करोड़ का खर्च राज्य सरकारें वहन करेंगी। इस खर्च का सबसे अधिक असर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर पड़ेगा। एक तरफ कांग्रेस मनरेगा का नाम न बदले जाने को लेकर एकजुट है। इस बिल के खिलाफ़ वोटिंग के लिए उसने अपने सांसदों को व्हिप जारी करने का निर्णय लिया है।

सांसत में सरकार भी प्रश्न इस बिल के पास होने या नहीं होने को ले कर नहीं है। सरकार मजबूत स्थिति में है इसलिए बिल के पास होने की संभावना अधिक है। हालांकि, आंध्र पर अधिक बोझ पड़ने को ले कर सांसत में सरकार भी है क्योंकि मौजूदा मोदी सरकार को आंध्र की तेलुगु देशम पार्टी का सपोर्ट है और इस बिल से आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भड़क भी सकते है। लेकिन यह भी माना जा रहा है, भाजपा ने इसका अंदाजा लगा ही लिया होगा और इसके बाद ही मंगलवार को कृषि मंत्री शिवराज चौहान लोकसभा में बिल लाए होंगे। राहुल गांधी की नामौजूदगी में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तरफ से कमान संभाली हुई है। उनकी हिंदी में कही बात पब्लिक को अधिक आकर्षित करती है। इसलिए अब देखना यह है कि मनरेगा के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटने और जी राम जी का नाम जुड़ने का क्या असर होगा। पर जी राम जी है कहां! यह भी दिलचस्प है कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा! सच यह है कि इस विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल में कहीं भी राम जी का नाम प्रत्यक्ष नहीं जोड़ा गया है। वह तो इस पूरे नाम को शॉर्ट में यूं लिखा गया है कि वह जी राम जी हो गया। आजीविका मिशन के आगे ग्रामीण शब्द जोड़ने के निहितार्थ यही है। अब भाजपा और कांग्रेस के इस ज़ुबानी जमा खर्च से आम व्यक्ति भी परेशान है। तब इस बिल को लेकर इतना हंगामा क्यों!

Rashtriya Sahara Page No-6